

दैनिक

राज्यल पत्रिका

वर्ष : 13

अंक : 312

पेज : 8

जयपुर, रविवार 19 अक्टूबर 2025

मूल्य: 1.50 रुपये

धनतेरस पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी

-स्वदेशी खरीदारी को बढ़ावा देने का आह्वान किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही, उन्होंने देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए भगवान धन्वंतरि से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए भगवान धन्वंतरि से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "देश के मेरे सभी परिवारजनों को धनतेरस की अनेकानेक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं हर किसी के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूँ। भगवान धन्वंतरि सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दें।"

भगवान धन्वंतरि से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करता हूँ: गृह मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "भगवान धन्वंतरि से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करता हूँ।" इस दौरान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया। देशवासियों के नाम अपने संदेश में उन्होंने लिखा, "सुख, समृद्धि और आरोग्य के पावन पर्व धनतेरस की आप सभी को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरि आपको स्वास्थ्य-धन प्रदान करें और माता लक्ष्मी आपको पर-आंगन को सुख, समृद्धि, धन-धान्य एवं वैभव से परिपूर्ण करें। इस



धनतेरस 'वोकल फॉर लोकल' को खरीदारी का मंत्र बनाइए। स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाइए।"

प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की जयंती की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की जयंती की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आरोग्य के देवता की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी का जीवन उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु व सुख-समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है।"

धनतेरस का पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उम्मीद और उन्नति का प्रकाश फैलाए: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संदेश में लिखा, "धनतेरस का पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उम्मीद और उन्नति का प्रकाश फैलाए। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख-समृद्धि बनी रहे और भगवान धन्वंतरि आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।"

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहला भव्य दीपोत्सव

-सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को किया आमंत्रित

नई दिल्ली (एजेंसी)। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के आगमन की गौरवमयी कथा को जीवंत करने का समय आ गया है। दिल्ली का कर्तव्य पथ शनिवार को पहली बार ऐतिहासिक दीपोत्सव की मेजबानी करने जा रहा है। 1 लाख 11 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य झोंन शो, राम कथा की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सनातन चेतना का संगम इस उत्सव को अविस्मरणीय बनाएगा। इसके साथ ही दिल्लीवासी और देशवासी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे।

18 अक्टूबर शाम 6 बजे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 1.11 लाख दीपों, भव्य झोंन शो, राम कथा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पहला दीपोत्सव मनाया जाएगा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक प्रेरणादायक संदेश साझा करते हुए दिल्लीवासियों को कर्तव्य पथ पर पहले दिव्य दीपोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह आयोजन आज, 18 अक्टूबर को शाम 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें 1 लाख 11 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य झोंन शो, राम कथा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी।

दीपों के सनातन संस्कृति के रंग में रंग देंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम के लौटने और रामलला के मंदिर में विराजने से भारत



की आत्मा पुनः जागृत हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संदेश में कहा, "अयोध्या में जब प्रभु श्रीराम लौटे थे, दीपों से पूरी धरती जगमगा उठी थी और जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजे, भारत ने अपनी आत्मा को फिर से पहचान लिया। वही चेतना, वही प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अवतरित होने जा रहा है। 1 लाख 11 हजार दीपों की श्रृंखला, दिव्य राम कथा, भव्य झोंन शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के संग, दिल्ली अपना पहला दिव्य दीपोत्सव मना रही है। यह उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है, जो युगों से यह संदेश देती आई है कि 'राम थे, राम हैं, और राम रहेंगे।' आइए, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनें। 18 अक्टूबर, शाम 6 बजे से कर्तव्य पथ पर आप सभी का स्वागत है।"

दीपावली से पहले एनसीआर में प्रदूषण चरम पर, नोएडा-गाजियाबाद में एक्वआई 300 पार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दीपावली से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्वआई) 300 के पार पहुंच गया है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में माना जाता है।

सेक्टर-62 में एक्वआई 244, सेक्टर-1 में 286, जबकि सेक्टर-116 में 290 तक पहुंच गया

कुछ क्षेत्रों में तो स्थिति इतनी खराब है कि एक्वआई ने लाल निशान को भी पार कर लिया है। नोएडा के विभिन्न इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा दर्ज किया गया। सेक्टर-62 में एक्वआई 244, सेक्टर-1 में 286, जबकि सेक्टर-116 में 290 तक पहुंच गया। सबसे खतरनाक स्थिति सेक्टर-125 में देखने को मिली, जहां एक्वआई 319 दर्ज हुआ, जो 'गंभीर' श्रेणी के बेहद करीब है।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, ओखला फेज-2 में एक्वआई 223, पूसा में 277 और मुनकद में 282 दर्ज हुआ

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ओखला फेज-2 में एक्वआई 223, पूसा में 277 और मुनकद में 282 दर्ज हुआ। वहीं वजीरपुर में एक्वआई 359, बवना में 312 और आनंद विहार में 379 तक पहुंच गया, जो सीधे तौर पर 'गंभीर' श्रेणी की चेतवानी देता है। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक्वआई 290 और इंदिरापुरम में 298, जबकि संजय नगर में

325 और लोनी में 351 दर्ज किया गया। पूरे जिले में औसतन वायु गुणवत्ता 300 के पार है, जिससे आम नागरिकों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वायु प्रदूषण की बढ़ती भयावहता को देखते हुए नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-1 लागू हो चुका है। वायु प्रदूषण की बढ़ती भयावहता को देखते हुए नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-1 लागू हो चुका है। सुबह से ही सड़कों पर प्राधिकरण की टीमों वॉटर स्प्रेयर के जरिए धूल नियंत्रण का प्रयास कर रही हैं। सड़कों की धुलाई, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कवरींग और कूड़ा जलाने पर सख्ती जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों से अपील की है कि बिना आवश्यकता बाहर न निकलें और यदि निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों, बुजुर्गों और सांस के रोगियों के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है।

भारत-मिस्र रिश्तों में बढ़ोतरी, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी और फिनटेक में सहयोग के अवसर खुलेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत और मिस्र के बीच रणनीतिक वार्ता इलेक्ट्रिक वाहनों, खाद्य सुरक्षा, रक्षा, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में सहयोग की अपार संभावनाओं के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाएगी।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वेस्ट एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमार को कोट करते हुए अरब न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दोनों देशों के बीच स्टार्टअप, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई, फिनटेक, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य सुरक्षा आदि जैसे उभरते और विशिष्ट क्षेत्रों सहित संबंधों को बेहतर बनाने की अपार संभावनाएं हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेश, ऊर्जा और रक्षा संबंध सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं

रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेश, ऊर्जा और रक्षा संबंध सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। मिस्र खासकर स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से स्थानीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने और निर्यात का विस्तार करने के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश के लिए उत्सुक है, जो व्यापक निवेश प्रोत्साहन और विभिन्न कर और सीमा शुल्क छूट प्रदान करता है।

मिस्र के विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देलाली दो दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता की सह-



अध्यक्षता की विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को दोनों देशों के बीच अपनी पहली रणनीतिक वार्ता के बाद कहा कि भारत और मिस्र स्टार्टअप, फिनटेक, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देलाली दो दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता की।

विदेश मंत्री जयशंकर ने 2023 में भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के बाद से गहन सहयोग की सराहना की

बिहार चुनाव 2025:

मतदान वाले दिन सभी को मिलेगा सवेतन अवकाश, चुनाव आयोग की घोषणा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों की तारीखों की घोषणा कर चुका है। मतदान



के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश जारी किया गया है। आयोग ने कहा कि यह कदम मतदाताओं को अपने वोट का इस्तेमाल करने में आसानी प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

बिहार में पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी

बिहार में पहला चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। इसके अलावा सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव भी 11 नवंबर को ही होंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत हर कर्मचारी, चाहे वह किसी व्यवसाय, उद्योग या अन्य प्रतिष्ठान में काम करता हो, मतदान के दिन सवेतन अवकाश पाने का हकदार है। इस दौरान उनकी तनखाह में कोई कटौती नहीं होगी। अगर कोई नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी इस सुविधा के हकदार हैं।

बिहार में इस घोषणा से कर्मचारियों और दैनिक मजदूरों में खुशी की लहर है

बिहार में इस घोषणा से कर्मचारियों और दैनिक मजदूरों में खुशी की लहर है। आयोग ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवकाश का लाभ देने में सहयोग करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। यह कदम मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तमिलनाडु के नौ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी: मौसम विभाग अलर्ट पर

तमिलनाडु (एजेंसी)। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने तमिलनाडु के नौ जिलों — कोयंबटूर, नीलगिरी, तिरुपुर, थेनी, डिंडीगुल, इरोड, सेलेम, नमकल और करूर — में भारी बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

शनिवार और रविवार को नीलगिरी, कोयंबटूर, तिरुपुर, इरोड, सेलेम, थेनी और तेनकासी में एक-दो स्थानों पर तेज़ बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि कुछ इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी संभव हैं। शुक्रवार सुबह तक के 24 घंटों में तिरुनेलवेली जिले के नाल्मुक्कू में सबसे ज़्यादा 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। ऊर्ध्व में 15 सेमी और काकाची में 14 सेमी बारिश हुई। लगातार बारिश से कुछ जगहों पर जलभराव और भूस्खलन की आशंका बढ़ी है। नीलगिरी जिला प्रशासन को संवेदनशील ढलानों और निचले इलाकों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। चेन्नई में भी बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है।

ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात तय:

दक्षिण कोरिया बनेगा अमेरिका-चीन ट्रेड वार का नया मंच

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिण कोरिया में होने जा रहे एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बहुप्रतीक्षित मुलाकात तय हो गई है। ट्रंप ने खुद पुष्टि की कि वे आने वाले कुछ हफ्तों में दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग से मिलेंगे। माना जा रहा है कि यह बैठक दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में अहम साबित हो सकती है।

हाल ही में चीन ने दुर्लभ मृदा धातुओं (Rare Earth Metals) के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा किया है। ये धातुएं रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उपकरणों में अत्यंत आवश्यक होती हैं। इस कदम से दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा, "चीन बातचीत करना चाहता है और हमें चीन से बात करना पसंद है। हमारे संबंध ठीक हैं और हम दक्षिण कोरिया में मिलने वाले हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनकी टैरिफ नीति के कारण अमेरिका "बहुत मजबूत स्थिति" में है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शी जिनपिंग से होने वाली इस मुलाकात में व्यापार समझौते की संभावना है। वहीं, ट्रंप ने चीन के निर्यात नियंत्रण कदम की निंदा करते हुए चेतावनी दी कि 1 नवंबर से चीनी वस्तुओं पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा और प्रमुख सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लागू किया जाएगा। फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "मेरी और शी जिनपिंग की एक अलग बैठक तय है। हम दक्षिण कोरिया में मिलेंगे, जहां कई अन्य देशों के नेता भी होंगे।" इस बैठक से उम्मीद की जा रही है कि यह

जीएसटी सुधारों से इस वर्ष खपत में 10% से अधिक वृद्धि की उम्मीद: केंद्र सरकार का दावा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने कहा है कि हाल ही में लागू किए गए जीएसटी सुधारों से देश की खपत और उपभोक्ता मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा रही है। 22 सितंबर से लागू नई जीएसटी दरों में कटौती का लाभ अब उपभोक्ताओं तक पहुंचने लगा है, जिससे त्योहारी सीजन में बाजारों में नई रौनक लौट आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और आईटी एवं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में बताया कि सुधारों के सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए हैं।

त्योहारी सीजन के बाद भी बनी रहेगी मांग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करों में की गई कटौती केवल त्योहारों के लिए अस्थायी राहत नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक प्रोत्साहन देना है। उन्होंने कहा, "जीएसटी सुधारों का असर यह दिखा रहा है कि अधिक संग्रह के बावजूद करदाताओं को राहत दी जा सकती है। इससे राजकोषीय स्थिति बेहतर हुई है और उपभोग को बल मिला है।" वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि जीएसटी विवाद समाधान तंत्र (Dispute Redressal Mechanism) प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। 2 अक्टूबर तक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी से संबंधित 3,981 कॉल दर्ज की गईं, जिनमें से 31 प्रतिशत पूछताछ और 69 प्रतिशत औपचारिक शिकायतें थीं। इनमें से लगभग 2,000 मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआईसी को भेजा गया, जबकि 761 शिकायतों का तत्काल समाधान किया गया। शिकायतों में जीएसटी कटौती के अनुपालन से जुड़ी गड़बड़ियां सीतारमण के अनुसार, अधिकांश शिकायतें जीएसटी दरों में की गई कटौती की समझ और वास्तविक अनुपालन के बीच के अंतर से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा

विदेश मंत्री जयशंकर ने 2023 में भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के बाद से गहन सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, समुद्री और आतंकवाद-रोधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

दोनों पक्ष डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, फार्मा, स्टार्टअप, इनोवेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश अवसर तलाशने पर सहमत हुए

पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत ने अरब न्यूज को बताया कि दोनों पक्ष डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, फार्मास्यूटिकल्स, स्टार्टअप और इनोवेशन के साथ-साथ रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमत हुए।

मिस्र के विदेश मंत्री अब्देलाली ने कहा कि स्वेज नहर क्षेत्र भारतीय कंपनियों के लिए निवेश अवसर है और वहां भारतीय औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना है स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र को भारतीय कंपनियों के लिए एक प्रमुख निवेश अवसर बताते हुए, मिस्र के विदेश मंत्री अब्देलाली ने कहा कि यह अंतरमहाद्वीपीय राष्ट्र लाल सागर के उत्तर-पश्चिम में स्वेज की खाड़ी के किनारे एक भारतीय औद्योगिक क्षेत्र बनाने का इच्छुक है।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध में कुछ राहत ला सकती है।



ट्रंप ने कहा, "हम सिर्फ निष्पक्ष व्यवहार चाहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और टैरिफ के कारण अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुरक्षित है।" उन्होंने दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि समान अवसरों के पक्ष में है।

हालांकि ट्रंप का रुख पहले की तुलना में कुछ नरम दिखा। उन्होंने शी जिनपिंग की प्रशंसा करते हुए कहा, "वह एक मजबूत नेता और अदृढ़ इंसान हैं।" साथ ही कहा, "हमें चीन के साथ एक निष्पक्ष समझौता चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें कई बार धोखा दिया है, अब यह स्थिति बदलनी चाहिए।" दक्षिण कोरिया में होने वाला यह शिखर सम्मेलन न केवल एशियाई अर्थव्यवस्था बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि दोनों देशों के बीच सहमति बनती है, तो वैश्विक बाजार को बड़ी राहत मिल सकती है।

जीएसटी सुधारों से इस वर्ष खपत में 10% से अधिक वृद्धि की उम्मीद: केंद्र सरकार का दावा



कि दवाओं और आवश्यक उपकरणों पर कर कटौती के बाद सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

ऑटोमोबाइल और ई-कॉमर्स सेक्टर में बढ़ी बिक्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जीएसटी सुधारों से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बड़ा फायदा हुआ है। कंपनियों ने उपभोक्ताओं तक राहत पहुंचाने के लिए वाहनों की कीमतें घटाईं, जिससे बिक्री में तेज़ी आई। उन्होंने कहा, "लगभग सभी प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भी नवरात्रि और त्योहारी ऑफर्स के दौरान जीएसटी कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया है।" गोयल ने आगे कहा, "अप्रत्यक्ष कर 140 करोड़ भारतीयों को प्रभावी करते हैं। जीएसटी दरों में कटौती के जरिए अब तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ दिया जा चुका है। इससे उपभोग, निवेश और उत्पादन—तीनों में सुधार हुआ है।"

10% से अधिक खपत वृद्धि की संभावना रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जीएसटी सुधारों के कारण उपभोग में इस वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है। उन्होंने कहा, "यह बढ़ोतरी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत के बराबर है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत सकारात्मक संकेत है।"

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

माओवादी संघर्ष का अंत: बंदूक से नहीं, संवाद और विकास से आरंभ असली बदलाव

भारत में माओवादी आंदोलन ने करीब तीन दशकों तक जिस सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया, आज उसी संघर्ष की निरर्थकता का एहसास आंदोलन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को होने लगा है। यह अहसास सिर्फ एक वैचारिक मोड़ नहीं, बल्कि हिंसा के रास्ते की सीमाओं का यथार्थ बोध है। भूपति जैसे माओवादी नेता का आत्मसमर्पण इस बात का प्रमाण है कि आखिरकार बंदूक से कोई स्थायी परिवर्तन संभव नहीं। माओवादी आंदोलन की शुरुआती जड़ें समाज में फैली असमानता, शोषण और अन्याय के खिलाफ पनपी थीं। उद्देश्य था — वंचितों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाना और विकास की मुख्यधारा में शामिल करना। लेकिन समय के साथ आंदोलन का स्वरूप बदलता गया। हिंसा, खून-खराबा और डर की राजनीति ने इसकी मूल भावना को कमजोर कर दिया। आंदोलन जनता की आवाज़ बनने के बजाय दहशत और विनाश का पर्यय बन गया। बीते वर्षों में माओवादी गतिविधियों के चलते हजारों निर्दोषों की जानें गईं, विकास कार्य ठप पड़ गए और प्रभावित इलाकों में डर का माहौल बन गया। लेकिन जब किसी विचारधारा की दिशा हिंसक हो जाती है, तो उसके भीतर से ही असंतोष जन्म लेने लगता है। यही असंतोष धीरे-धीरे आत्मचिंतन में बदलता है और फिर एक दिन यह बोध कराता है कि हिंसा से बदलाव नहीं, विनाश होता है। भूपति का आत्मसमर्पण केवल एक व्यक्ति

का कदम नहीं, बल्कि एक विचार की हार और मानवीय संवेदना की जीत है। वह संगठन का दिमाग कहे जाने वाला, छह करोड़ के इनामी और पोलित ब्यूरो (सेंट्रल कमिटी) का सदस्य था। जब ऐसे बड़े स्तर का नेता यह स्वीकार करता है कि बंदूक से समाज नहीं बदल सकता, तो यह संदेश नीचे तक गूँजता है। इससे अन्य माओवादी कार्यकर्ताओं के भीतर भी आत्ममंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के दोहरे प्रयासों को जाता है। एक ओर सुरक्षा बलों ने सटीक खुफिया तंत्र, आधुनिक हथियारों और योजनाबद्ध रणनीति के जरिए माओवादी इलाकों में दबदबा कायम किया है, वहीं दूसरी ओर समर्पण करने वालों के लिए पुनर्वास नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। यह नीति न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि आत्मसमर्पण करने वालों को समाज में दोबारा सम्मानजनक जीवन जीने का मौका भी देती है। सरकारों ने यह समझा कि केवल गोली से नहीं, बल्कि संवाद और विकास से ही इस समस्या का समाधान संभव है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली और रोजगार जैसे बुनियादी ढांचे को सुधारने से माओवादी इलाकों में लोगों का विश्वास शासन पर बढ़ा है। यही वजह है कि अब आम जनता भी हिंसा से दूरी बनाकर विकास के रास्ते को प्राथमिकता दे रही है। यह स्पष्ट है कि हिंसक संघर्ष की कोई स्थायी उपयोगिता नहीं होती।

रिश्वतखोरी का खेल: भारत में घूसखोरी उजागर करने पर सुधार की बजाय अक्सर प्रतिशोध देवने को मिलता है

-जब ईमानदारी बन जाए खतरा — संस्थागत भ्रष्टाचार, प्रतिशोध और सुधार की जद्दोजहद के बीच फँसा भारतीय व्यवसायिक तंत्र

भारत की आर्थिक नीतियाँ और व्यापारिक माहौल जितना तेजी से बदल रहे हैं, उतनी ही तीव्रता से उन पर संस्थागत बाधाएँ और भ्रष्टाचार की जड़ें असर डालती दिखाई देती हैं। सुधार के नाम पर शुरू किए गए कदम, जीएसटी से लेकर निर्यात-प्रोत्साहन तक, अगर जमीन पर पारदर्शिता और नियमों के सही-सही पालन से नहीं जुड़ते तो वे सिर्फ कागज़ी कवायद बनकर रह जाते हैं। हालिया दिनों में एक ऐसा मामला उभरा है जिसने यह संकेत और भी तेज़ कर दिया — विनट्रैक (Wintrack Inc.) का आरोप कि उसने चेन्नई कस्टम्स में दो बार रिश्वतखोरी उजागर की, और इसके बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिशोध कर कंपनी के व्यापार को 'प्रभावी ढंग से नष्ट' किया गया — जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने भारत में अपने इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट ऑपरेशन्स बंद करने की घोषणा कर दी। यह मामला केवल एक व्यापारिक विवाद नहीं है; यह उस भयावह संदेश का प्रतीक है जो घूसखोरी उजागर करने वालों को मिलता है — सुधार की उम्मीद के बजाय बदले की भावना। नीचे इस लेख में हम समस्या की तह तक उतरने की कोशिश करेंगे — किन-किन तरीकों से रिश्वतखोरी भारत के कारोबारी और आम जीवन को प्रभावित करती है, जब कोई घूसखोरी को उजागर करता है तो क्या व्यवहारिक dificultades (मुश्किलें) आती हैं, और किन-किन कारणों से हम इस दुष्प्रक्रिया को तोड़ सकते हैं। लिखते समय मैंने कोशिश की है कि भाषा सरल रहे, आम लोग आसानी से समझ सकें और लेख में कुछ जगहों पर रोज़मर्रा की बोलचाल की उर्दू-

भाव-प्रकट करने में असर रहे। **समस्या की पृष्ठभूमि: भ्रष्टाचार की परिभाषा और उसे उजागर करने का खतरा** भ्रष्टाचार साधारण शब्दों में वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक पदों, नियमों या प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर निजी लाभ प्राप्त किया जाए — नकद रिश्वत, बेनामी लेन-देन, नज़राना, फेवरेटिज़्म (नफ़रत-रहित तरज़ीह) वगैरह। पर यह सिर्फ़ पैसों का खेल नहीं; यह भरोसे के साथ भी खेलता है — जब दे रहा व्यक्ति और ले रहा अधिकारी दोनों सिस्टम के भीतर नियमित तौर पर एक ख़ास भ्रष्टाचार की समझदारी बना लेते हैं, तो वह व्यवस्था 'नियमों से ज़्यादा रिश्वत' को चलने लगती है। ऐसे में जो कोई इस व्यवस्था के खिलाफ़ आवाज़ उठाता है, उसे अक्सर

अकेला, असुरक्षित और निशाने पर पाता है। विनट्रैक का मामला भर में पारदर्शिता की हालत अभी भी कमजोर है और कई देशों की

विदेशी निवेश झिझकता है, और घरेलू निवेशकों की चुस्ती—दुर्मु (उद्योग से हटने की प्रवृत्ति) बढ़ती है। पर ह की क त : कारोबारी छिन्दगी और छोटे-बड़े हादसे भारत में कारोबारी शुरू करना और चलाना आधिकारिक तौर पर सरल हो सकता है—नए नियम, डिजिटलीकरण, ई-निवेदन प्रणाली आदि। लेकिन जमीन पर कई बार ऐसा नहीं

दिखता। जमीन खरीदने से लेकर फ़ैक्ट्री का लाईसेंस लेने, फ़ायर एनओसी और बिजली कनेक्शन तक — हर स्टेप के पीछे दलाल (इंटरमीडियरी), अधिकारी की मनमानी, और कई बार रिश्वतखोरी की उम्मीद बैठी रहती है। छोटे व्यापारी के सामने यह दुविधा रहती है कि नियमों का पालन कर कर अपना काम धीमा कर लें या त्वरित निपटान के लिए 'नज़राना' दें और बाजार में टिके रहें। यह समस्या सिर्फ़ बड़े नक़दी के मामले नहीं; नियमित, छोटे-छोटे भुगतान जो 'नामी' नहीं होते—वो भी कारोबारियों की लागत बढ़ा देते हैं और असल में वे उपभोक्ता की जेब पर असर डालते हैं। इन छोटे-छोटे भुगतान का भार जमा होकर आखिरकार महंगाई और सेवाओं की घटती गुणवत्ता में बदल

जाता है। व्यापारियों के लिए सबसे ज़्यादा पीड़ादायक पक्ष यह है कि जब वे भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो उन्हें अक्सर वैसा प्रतिशोध झेलना पड़ता है जो उनके अस्तित्व को ही खतरों में डाल दे—बिना किसी ट्रांसपेरेंट जांच के कागज़ों पर अभियोग, कस्टम्स में देरी, शिपमेंट रोकना, लाइसेंस रोकना आदि। विनट्रैक के आरोपों में भी इसी तरह की प्रक्रियात्मक प्रताड़ना का जिक्र है — कंपनी का कहना है कि शिकायत के बाद प्रतिशोध के तौर पर उनके शिपमेंट रोक दिये गए और व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया गया। **घूसखोरी उजागर करने वालों का डर — प्रतिशोध के रूप** घोषित और अनघोषित प्रतिशोध के कई रूप होते हैं: प्रक्रियात्मक देरी: कस्टम्स, लाइसेंस या अन्य विभागों में जानबूझकर फाइलों पर देरी करना ताकि व्यापार या सेवा देरी से प्रभावित हो। दंडात्मक कार्रवाई: नियमों का अनुपालन न करने के कथित आरोप लगाकर जुर्माना, छापेमारी, या व्यवसायिक पहचान को क्षति पहुँचाना। सूचनाओं का लीक/बेहद नकारात्मक प्रचार: झूठे आरोपों के ज़रिये कंपनी या व्यक्ति की छवि खराब करना। कानूनी उलझनें: फ़र्जी मामलों का पल्ला कर कानूनी लड़ाइयों में उलझा देना, जिससे आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़े। रिश्वत मांगना और फिर न दिए जाने पर हर्जाना देना: पहली मांग पूरी न होने पर विभिन्न तरह से कारोबार को प्रभावित करना। विनट्रैक के विवाद में इन चिह्नों का एक मिश्रित रूप देखा गया — कंपनी ने दावा किया कि जानबूझकर हो रही परेशानियों से उनका कारोबार ठप हो गया।

बाताता है कि किसी भी कंपनी द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर अगर जांच करने वाले संस्था या विभाग जवाबदेही नहीं निभाते, या दर्ज शिकायतकर्ता के खिलाफ़ प्रक्रियात्मक कार्यवाही कर देते हैं, तो परिणाम विनाशकारी होते हैं — व्यापार बंद, रोज़गार प्रभावित, और निवेश का माहौल खराब। साथ ही, ऐसे मामलों से एक chilling effect (डर का माहौल) बनता है — यानी दूसरे कारोबारी और नागरिक भी चुप रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि आवाज़ उठाने पर उनको नुकसान होगा। **ऑकड़े और रुझान: अंतरराष्ट्रीय नज़रिया और भारत का स्थान** ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का 'Corruption Perceptions Index (CPI) 2024' बताता है कि दुनिया

में 180 देशों में 96वें स्थान पर है, और उसका स्कोर 38 है — जो 2023 के 93वें स्थान (स्कोर 39) और 2022 के 85वें स्थान (स्कोर 40) से गिरावट दर्शाता है। इसका अर्थ केवल रैंक का नहीं; यह संकेत है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की पारदर्शिता पर अब दुनिया की नजर अधिक आशंकित होकर रख रही है। ऐसे ऑकड़े देश की साक्ष, निवेश की आकर्षकता और नीति-निर्माण की विश्वसनीयता पर असर डालते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रेटिंग और स्कोर सिर्फ़ संख्या नहीं; ये संकेत देते हैं कि रोज़मर्रा के नागरिक, व्यापारी और निवेशक कितनी जल्दी सरकारी प्रक्रियाओं पर भरोसा कर पाएँगे। जब भरोसा कम होता है, पूँजी बाहर जाती है,

रेटिंग गिर रही है। भारत इस सूची में 180 देशों में 96वें स्थान पर है, और उसका स्कोर 38 है — जो 2023 के 93वें स्थान (स्कोर 39) और 2022 के 85वें स्थान (स्कोर 40) से गिरावट दर्शाता है। इसका अर्थ केवल रैंक का नहीं; यह संकेत है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की पारदर्शिता पर अब दुनिया की नजर अधिक आशंकित होकर रख रही है। ऐसे ऑकड़े देश की साक्ष, निवेश की आकर्षकता और नीति-निर्माण की विश्वसनीयता पर असर डालते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रेटिंग और स्कोर सिर्फ़ संख्या नहीं; ये संकेत देते हैं कि रोज़मर्रा के नागरिक, व्यापारी और निवेशक कितनी जल्दी सरकारी प्रक्रियाओं पर भरोसा कर पाएँगे। जब भरोसा कम होता है, पूँजी बाहर जाती है,

रेटिंग गिर रही है। भारत इस सूची में 180 देशों में 96वें स्थान पर है, और उसका स्कोर 38 है — जो 2023 के 93वें स्थान (स्कोर 39) और 2022 के 85वें स्थान (स्कोर 40) से गिरावट दर्शाता है। इसका अर्थ केवल रैंक का नहीं; यह संकेत है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की पारदर्शिता पर अब दुनिया की नजर अधिक आशंकित होकर रख रही है। ऐसे ऑकड़े देश की साक्ष, निवेश की आकर्षकता और नीति-निर्माण की विश्वसनीयता पर असर डालते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रेटिंग और स्कोर सिर्फ़ संख्या नहीं; ये संकेत देते हैं कि रोज़मर्रा के नागरिक, व्यापारी और निवेशक कितनी जल्दी सरकारी प्रक्रियाओं पर भरोसा कर पाएँगे। जब भरोसा कम होता है, पूँजी बाहर जाती है,

रेटिंग गिर रही है। भारत इस सूची में 180 देशों में 96वें स्थान पर है, और उसका स्कोर 38 है — जो 2023 के 93वें स्थान (स्कोर 39) और 2022 के 85वें स्थान (स्कोर 40) से गिरावट दर्शाता है। इसका अर्थ केवल रैंक का नहीं; यह संकेत है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की पारदर्शिता पर अब दुनिया की नजर अधिक आशंकित होकर रख रही है। ऐसे ऑकड़े देश की साक्ष, निवेश की आकर्षकता और नीति-निर्माण की विश्वसनीयता पर असर डालते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रेटिंग और स्कोर सिर्फ़ संख्या नहीं; ये संकेत देते हैं कि रोज़मर्रा के नागरिक, व्यापारी और निवेशक कितनी जल्दी सरकारी प्रक्रियाओं पर भरोसा कर पाएँगे। जब भरोसा कम होता है, पूँजी बाहर जाती है,

एनसीआरबी रिपोर्ट में अपराध पीड़ितों को मिले मुआवज़ों के आंकड़े भी शामिल किए जाएं

-न्याय से परे सवाल: क्या हर अपराध पीड़ित को मिला मुआवज़ा?

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताज़ा रिपोर्ट 'भारत में अपराध-2023' के अनुसार देश में वर्ष 2023 में कुल 62,41,569 संज्ञेय अपराध दर्ज हुए। यह संख्या केवल कागज़ों पर दर्ज मामलों का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इसके पीछे करोड़ों ज़िंदगियों की पीड़ा, अन्याय, और असुरक्षा की कहानियाँ छिपी हैं। अपराध का असर केवल अपराधी और पीड़ित तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज में डर, अविश्वास और असमानता का वातावरण पैदा करता है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ पहले से गहरी हैं, वहाँ अपराध का दंश सबसे ज़्यादा उन लोगों को झेलना पड़ता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और कानूनी रूप से असुरक्षित हैं। किसी अपराध के बाद जब कोई परिवार अपने सदस्य को खो देता है — खासकर अगर वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति हो — तो वह केवल भावनात्मक नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट बन जाता है। **अपराध पीड़ित को मुआवज़ा: न्याय का आवश्यक हिस्सा** आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल अपराधी को सज़ा देना नहीं, बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाना भी है। न्याय का यह दूसरा पहलू अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है। मुआवज़ा (Compensation) इसी न्याय का व्यावहारिक और मानवीय रूप है, जो पीड़ित या उसके आश्रितों को अपराध से हुए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के रूप में दिया जाता है। भारत में अपराध पीड़ितों के लिए मुआवज़े का कानूनी आधार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) — जिसे पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrP) कहा जाता था — में स्पष्ट रूप से दिया गया है। धारा 395 और 396 इसी उद्देश्य से बनाए गए प्रावधान हैं। **धारा 395 - अदालत द्वारा मुआवज़ा देने का प्रावधान** धारा 395 के तहत, जब किसी



अपराधी को सज़ा दी जाती है और उस सज़ा में जुर्माना का प्रावधान शामिल होता है, तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि उस जुर्माने की पूरी या कुछ राशि अपराध पीड़ित या उसके वारिसों को मुआवज़े के रूप में दी जाए। यदि सज़ा में जुर्माना शामिल नहीं है, तब भी अदालत अपने विवेक के तहत पीड़ित राशि को मुआवज़े के रूप में तय कर सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध से प्रभावित व्यक्ति को केवल भावनात्मक न्याय न मिले, बल्कि उसे व्यवहारिक राहत भी मिले — जिससे वह अपने जीवन को दोबारा व्यवस्थित कर सके। **धारा 396 - 'पीड़ित मुआवज़ा योजना' (Victim Compensation Scheme)** धारा 396 में एक व्यापक 'पीड़ित मुआवज़ा योजना' का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना अनिवार्य है। इस योजना के तहत अपराध से प्रभावित व्यक्ति या उसके आश्रितों — जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप चोट, हानि या जीवन-यापन की कठिनाई हुई हो — को पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि अदालत यह पाती है कि धारा 395 के तहत दिया गया मुआवज़ा पर्याप्त नहीं है, या आरोपी के दोष

सिद्ध न हो पाने की स्थिति में भी, वह राज्य की पीड़ित मुआवज़ा योजना के तहत पीड़ित को उचित राशि देने की सिफारिश कर सकती है। **मुआवज़ा देने की आवश्यकता क्यों है?** भारत में अपराध का सबसे भयावह पहलू यह है कि न्याय मिलने तक का सफर बहुत लंबा होता है। कई बार तो अदालत में वर्षों तक मुकदमा चलता रहता है। इस दौरान पीड़ित परिवार को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक दबाव भी झेलना पड़ता है। ऐसे में मुआवज़ा सिर्फ़ राशि नहीं, बल्कि राज्य की संवेदनशीलता और जाबजबादगी का प्रतीक है। यह बताता है कि सरकार अपराध पीड़ितों के साथ खड़ी है और उन्हें पुनर्वास का अधिकार देती है। मुआवज़ा पीड़ित के लिए जीवन में नई शुरुआत का अवसर हो सकता है — चाहे वह किसी रेप पीड़िता का मानसिक और आर्थिक पुनर्वास हो, किसी दुर्घटना में परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु का मामला हो, या किसी बच्चे के खिलाफ़ हिंसा का अपराध। **न्याय प्रणाली और एनसीआरबी का सीमित दृष्टिकोण** नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) देश में अपराध से

जुड़ी विस्तृत सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी करता है। इन रिपोर्टों में अपराधों की संख्या, उनकी प्रकृति, राज्यों में अपराध दर, पुलिस कार्रवाई, चार्जशीट, और सज़ा दर जैसी जानकारी विस्तार से दी जाती है। लेकिन एक बड़ी कमी यह है कि इन रिपोर्टों में अपराध पीड़ितों को शामिल नहीं किए जाते। यह प्रश्न बहुत अहम है कि — 'क्या हर अपराध पीड़ित को मुआवज़ा मिला? और अगर नहीं मिला, तो क्यों नहीं?' एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर अपराध के वास्तविक प्रभाव को समझना चाहती है, तो केवल अपराध की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं। उसे यह भी बताना चाहिए कि उन अपराधों के बाद पीड़ितों के साथ क्या हुआ — कितनों को न्याय मिला, कितनों को पुनर्वास मिला, और कितनों को मुआवज़ा मिला या नहीं मिला। **मुआवज़ा योजनाओं की स्थिति** भारत के सभी राज्यों में पीड़ित मुआवज़ा योजनाएँ लागू हैं, लेकिन उनकी कार्यक्षमता बेहद असमान है। कई राज्यों में मुआवज़े के लिए जबकि प्रक्रिया इतनी जटिल है कि पीड़ित वर्षों तक न्यायालयों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है।

“शिक्षा सत्र की शुरुआत से ही बच्चों को किताबें मिलनी चाहिए”

-समय पर पाठ्यपुस्तक वितरण ही सच्ची शिक्षा व्यवस्था की पहचान

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शिक्षा न केवल अधिकार है, बल्कि एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत भी है जो हर बच्चे के भविष्य की दिशा तय करती है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों में शिक्षा व्यवस्था में समयबद्धता की सबसे बड़ी चुनौती पाठ्यपुस्तकों की देरी से आपूर्ति बनी हुई है। जब शिक्षा सत्र शुरू हो जाता है और बच्चे उत्साह से स्कूल पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें किताबें नहीं मिलती — तो उनकी सीखने की लय टूट जाती है। यह न केवल छात्रों के उत्साह को कम करता है, बल्कि अध्यापकों और अभिभावकों के मन में भी निराशा भर देता है। **पिछले सत्र की हकीकत: देरी का सबक** पिछले सत्र में राज्य के अधिकांश सरकारी स्कूलों में किताबें लगभग दो माह की देरी से पहुँचीं। इस दौरान कई जगहों पर स्थिति इतनी खराब रही कि स्कूलों को मजबूरी में फोटोकॉपी से बच्चों को पढ़ाना पड़ा। कई शिक्षकों ने स्वयं अपने-पैसे से फोटो कॉपी कराकर बच्चों तक सामग्री पहुँचाई ताकि उनकी पढ़ाई पूरी तरह बाधित न हो। इतना ही नहीं, कई जिलों में प्रारंभिक परीक्षाएँ बिना किताबों के ही आयोजित करनी पड़ीं। यह एक ऐसी स्थिति थी जो शिक्षा प्रणाली की जड़ों को हिलाने वाली थी। इस अनुभव ने विभाग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि "सिर्फ़ कागज़ी तैयारी" से कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक स्कूल के पहले दिन हर बच्चे के हाथ में किताब नहीं होगी, तब तक सरकार की 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' की बात अधूरी ही रहेगी। **देरी के कारण: समस्या की जड़ें गहरी हैं** किताबें स्कूलों तक समय पर नहीं पहुँच पाने के पीछे कई वजहें हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ करना भारी गलती होगी। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: **पाठ्यक्रम में बार-बार बदलाव:** हर साल पाठ्यक्रम में सुधार या नए विषय जोड़ने के नाम पर बदलाव किए जाते हैं। पाठ्य सामग्री को अंतिम रूप देने में महीनों लग जाते हैं, जिससे छपाई का समय कम हो जाता है। **प्रशासनिक मंजूरी और बजट की देरी:** अक्सर वित्तीय स्वीकृति और

बजट आवंटन की प्रक्रिया लंबी हो जाती है। जब तक टेंडर जारी होता

विकसित शिक्षा प्रणाली के लिए शर्मनाक कही जा सकती है।

आज के डिजिटल युग में जब हर सरकारी योजना का रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव है, तो किताबों के वितरण को भी डिजिटल टैकिंग सिस्टम से क्यों न जोड़ा जाए? अगर हर चरण — मांग, छपाई, पैकिंग, परिवहन और वितरण — को डिजिटल सिस्टम पर टैक



है, तब तक समय हाथ से निकल जाता है। छपाई से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें: सरकारी प्रेस या अनुबंधित निजी प्रेसों में मशीनों की क्षमता सीमित होती है। एक साथ लाखों पुस्तकों की छपाई में तकनीकी अड़चनें आना स्वाभाविक है। वितरण नेटवर्क की कमजोरी: किताबें छप जाने के बाद भी स्कूलों तक पहुँचाने की प्रक्रिया में देरी होती है। ट्रांसपोर्ट, गोदाम और क्षेत्रीय वितरण केंद्रों में समन्वय की कमी से समय बर्बाद होता है। मांग और आपूर्ति का गलत अनुमान: नामांकन के आंकड़े कई बार पुराने आधार पर तैयार होते हैं, जिससे किताबों की संख्या का सटीक अनुमान नहीं लग पाता। नतीजतन कुछ स्कूलों में किताबों की कमी और कुछ में अधिकता देखने को मिलती है। अनुबंध प्रक्रिया में विलंब: टेंडर जारी करने से लेकर सप्लाय ऑर्डर जारी करने तक की प्रक्रिया में औपचारिकताओं का लंबा सिलसिला चलता है। जब तक यह पूरी होती है, सत्र शुरू हो चुका होता है। **फोटोकॉपी से पढ़ाई: एक मजबूरी नहीं, एक विफलता** शिक्षा सत्र की शुरुआत में जब किताबें नहीं पहुँचीं, तो कई स्कूलों ने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए फोटोकॉपी या हस्तलिखित नोट्स का सहारा लिया। लेकिन क्या यही शिक्षा का असली रूप है? जब बच्चा किताब हाथ में लेकर खुद पढ़ता है, पन्ने पलटता है, चित्र देखता है — तभी उसमें पढ़ने की रुचि पैदा होती है। फोटोकॉपी की सीमित पन्नों में यह अनुभव खत्म हो जाता है। यह स्थिति किसी भी

समय पर किताबें क्यों ज़रूरी हैं किताबें केवल पढ़ने का साधन नहीं, बल्कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण का आधार हैं। समय पर किताबें मिलने से: पढ़ाई की निरंतरता बनी रहती है। अध्यापक सत्रवार पाठ्यक्रम योजना के अनुसार पढ़ा पाते हैं। बच्चों में अध्ययन के प्रति उत्साह बना रहता है। अभिभावकों का सरकारी स्कूलों पर भरोसा बढ़ता है। नि:शुल्क वितरण से नामांकन दर में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को शुरुआती बढ़त मिलती है। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह किताबों के वितरण को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखे। **सरकारी तैयारी: उम्मीद की किरण** यह राहत की बात है कि शिक्षा विभाग ने इस बार जनवरी से पहले ही मांग पत्र जारी कर दिए हैं। पिछले वर्षों के अनुभवों से सबक लेते हुए, विभाग ने प्रस्ताव किया है कि छपाई पहले शुरू की जा सके। साथ ही चर्चा है कि आगामी सत्र की शुरुआत में भी कुछ बदलाव संभव हैं — यानी सत्र पहले शुरू किया जा सकता है। ऐसे में किताबों की ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा पहले पड़ेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि विभाग सिर्फ़ "कागज़ी तैयारी" तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी अमल पर ध्यान दे। तैयारी का अर्थ केवल फाइलों में नोटिंग करना नहीं, बल्कि तय समय पर छपाई और वितरण सुनिश्चित करना है। **डिजिटल टैकिंग सिस्टम: समाधान की दिशा**

किया जाए, तो देरी के कारण तुरंत पहचान में आ जाएंगे। राज्य स्तर पर एक ई-पुस्तक पोर्टल बनाकर हर जिले की स्थिति को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जवाबदेही भी तय होगी। जिन जिलों में देरी होगी, वहाँ जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लिया जा सकेगा। **शिक्षकों की भूमिका और जवाबदेही** किताबें समय पर पहुँचें, यह सिर्फ़ विभाग का काम नहीं, बल्कि स्कूल प्रशासन और शिक्षकों की जिम्मेदारी भी है। प्रत्येक स्कूल में एक पुस्तक प्रभारी शिक्षक नियुक्त किया जा सकता है जो जिले के शिक्षा अधिकारी के साथ लगातार संवाद में रहे। शिक्षक अगर समय पर मांग का प्रस्ताव भेजें, पुराने स्टॉक का सही हिसाब रखें और वितरण का रिकॉर्ड ऑनलाइन भरें, तो पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित रह सकती है। यह तभी संभव है जब शिक्षकों को प्रशासनिक काम के बोझ से थोड़ा बचका दिया जाए और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। अक्सर देखा गया है कि किताबों की छपाई और वितरण से जुड़ा बजट अलग-अलग स्तरों पर फंस जाता है। टेंडर जारी करने में देरी या फाइलों का अटक जाना एक आम समस्या है। इस स्थिति से बचने के लिए शिक्षा विभाग को एक समर्पित 'बुक प्रोडक्शन सेल' बनाना चाहिए, जो केवल पाठ्यपुस्तक छपाई और वितरण पर निगरानी रखे। शिक्षा प्रणाली का केंद्रबिंदु बच्चा होना चाहिए, न कि फाइलें और प्रक्रियाएँ।

भजनलाल शर्मा ने 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में 718 करोड़ रुपये किए हस्तान्तरित

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र निर्माता और भारत की आत्मा हैं। कृषक जब अपने खेतों में दिन-रात मेहनत करता है, तभी हमारी थाली में भोजन आ पाता है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता शब्द समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। हमारा किसान समृद्ध होगा तो देश और प्रदेश भी विकसित होगा, इसलिए राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। शर्मा ने शनिवार को भरतपुर के नदबई में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्य के लगभग 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपये की राशि का हस्तान्तरण किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सर्वोपरि मानते हुए उनके कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ की। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पौने दो साल में किसानों को 7 हजार 31 करोड़ रुपये से अधिक दिए जा चुके हैं। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार के अतिरिक्त 3 हजार की राशि अलग से प्रदेश के किसानों को देती है। इसके तहत अब तक 70 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 355 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि



के तहत किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है जो एक रिकॉर्ड है। इसी क्रम में चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपये किसानों को और दिए गए हैं। **पीएम धन-धान्य कृषि योजना में राज्य के 8 जिले शामिल—** मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि की गई पीएम धन धान्य कृषि योजना प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की परिचायक है। देशभर से चयनित 100 जिलों में राज्य के आठ जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य केवल उत्पादकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना भी है। **दो वर्ष में जारी की गई 7.50 करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी—** शर्मा ने किसानों को परम्परागत खेती के साथ ही, आधुनिक खेती भी अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा

योजना के तहत बीते दो वर्षों के दौरान राज्य में साढ़े सात करोड़ से अधिक फसल बीमा पॉलिसी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि 3 हजार 452 करोड़ रुपये का राज्यांश प्रीमियम जमा कराया गया तथा 5 हजार 965 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए गए। पारदर्शिता के लिए इस योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी किसान इस सुविधा से वंचित न रहे। इसके लिए लगभग 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन किया जा चुका है और लगभग 75 लाख किसानों की आधार सीडिंग तथा 71 लाख किसानों का ई-केवाईसी कार्य पूरा हो चुका है। **77 लाख किसानों को मिले अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण—** मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 77 लाख से अधिक हजार किसानों को 43 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि के अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण दिए हैं। साथ ही, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में करीब 71 हजार पशुपालकों को 515 करोड़

रुपये का ऋण तथा चालू वित्त वर्ष में 2 हजार 855 सदस्यों को दीर्घकालीन सहकारी कृषि और नॉन-फार्मिंग सेक्टर पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 103 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। **पीएम कुसुम योजना में 50 हजार से अधिक सौर पंप सेट की हुई स्थापना—** शर्मा ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट-बी के तहत राजस्थान में लगभग 50 हजार से अधिक सौर पंप सेट की स्थापना पर 733 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। राज्य में 1 लाख 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और मिनी फव्वारा सेट स्थापित कर 1 लाख किसानों को 740 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सेट स्थापित कर 1 लाख 13 हजार किसानों को 227 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। प्याज के उचित भंडारण के लिए लगभग 2 हजार 583 प्याज भंडार गृहों की स्थापना हेतु 44 करोड़ रुपये तथा 97 हजार कृषि यंत्रों पर 546 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ ही, 9 हजार 205 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं।

जनभागीदारी से हो जनकल्याण, योजनाओं की हो सफल क्रियान्विति - झाबर सिंह खर्रा

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को चूरू नगरपरिषद स्थित परशुराम भवन में आयोजित शहरी सेवा शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लाभार्थियों को पट्टे व पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति के चेक सौंपे। शिविर में चूरू विधायक हरलाल सहाण, जिला प्रमुख श्रीमती वंदना आर्य, जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा सहित अधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। खर्रा ने शिविर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हम प्रदेश को विकसित बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने आमजन को बेहतरीन सुविधाएं एक ही जगह मुहैया करवाने के लिए सेवा शिविरों का संचालन किया है। खर्रा ने जानकारी दी कि स्वायत्त शासन विभाग सभी प्रकार की सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन लेने के लिए तकनीकी तैयारी कर चुका है। आवास योजनाओं व भूखंडों के स्वामित्व की जानकारी भी ऑनलाइन ही की जाएगी ताकि कोई भी नागरिक भूखंड के वास्तविक मालिक को देख सकेगा। इससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के 10 हजार गांवों को गरीबी मुक्त गांव बनाने के सतत प्रयास कर रही है। इसी के साथ पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना व उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से आम आदमी की आमदनी बढ़ाने



और उनके आर्थिक सशक्तीकरण का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में खर्रा ने संग्राम सिंह राठौड़, जगदीश सिंह, सीताराम पीपलवा व मनोज कुमार शर्मा को भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान की। सुमन, ममता, सुनील कुमार, अजय सिंह, रतनलाल, ईदिरा कुल्हरी, सुशीला कुमारी, कुलदीप ईशराण, अमीर खान, बनवारीलाल नायक आदि को नामांतरण तथा हरिप्रसाद सैनी, महेंद्र सिंह, खेताराम, सरोज, विद्याधर, आदित्य, तनसुखराम, रामगोपाल, राममोहन मंत्री, सावन परिहार, प्रीति अग्रवाल, अनीता मीणा, गौरव जांगिड़, कैलाश कर्वा, प्रियंका अग्रवाल, शिल्पा बजाज, पंकज अग्रवाल, सुशील कुमार, किरण कंवर, ईशरज कंवर, पुष्पेंद्र सिंह, महावीर सिंह धांधनिया आदि को पट्टे प्रदान किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में जगदीश, सुशी मोहम्मद, विनोद, राजू व मोहम्मद को 50-50 हजार रुपए की प्रथम किश्त के चेक तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 अंतर्गत रचना व लेखचंद को आवास पूर्ण होने पर चाबी सौंपी। इसी के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत जाकिर, आरिफ, सरोज, संदीप गाड़िया लोहार, सुनीता, सुमन, पंकी देवी को 25000 रुपए राशि का ऋण स्वीकृति चेक प्रदान किया और टीबी मरीजों को निश्चय पोषण किट दिए।

ऑल इण्डिया वक्फ संपत्ति संरक्षण बोर्ड ने की नई नियुक्तियां

-आफताब हिंदुस्तानी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। गुरुवार 16 अक्टूबर को जयपुर में ऑल इण्डिया मुस्लिम वक्फ संपत्ति संरक्षण बोर्ड की मीटिंग आयोजित हुई जिसमें राजस्थान प्रदेश कार्यकारी के संगठन को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई एवं कई अहम फैसले लिए गए एवं कई नियुक्तियां भी की गईं। मीटिंग में मिर्जा आफताब बैग हिंदुस्तानी को ऑल इण्डिया वक्फ संपत्ति संरक्षण बोर्ड का राजस्थान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा माजिद खान पठान को प्रदेश मुख्य संगठन महामंत्री, अकरम कुरेशी को प्रदेश उपाध्यक्ष, गुलजार कुरेशी को प्रदेश मंत्री, नवाब कुरेशी को जयपुर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। मीटिंग में राष्ट्रीय महामंत्री अब्दुल रईस, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य मोहम्मद अशरफ कुरेशी, मोहम्मद हुसैन, जुनेद अख्तर (आसिफ), हजरत हामिद फारूकी, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद रमीज कुरेशी उपस्थित हुए। ऑल इण्डिया वक्फ संपत्ति संरक्षण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एड. रहीस अहमद कुरेशी ने मीटिंग की अध्यक्षता की तथा बोर्ड के मुख्य खान पठान को प्रदेश मुख्य अतिथि उपस्थित हुए।



अंता विधानसभा उपचुनाव 2025: भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के नामांकन में शामिल हुए हमीद खान मेवाती



अंता (रॉयल पत्रिका)। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत शनिवार को भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती विशेष रूप से उपस्थित रहे। नामांकन कार्यक्रम में सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य डॉ. मजीद मलिक कर्मांडो, विधायक ललित मीणा, पूर्व विधायक हेमराज मीणा, अंता (रॉयल पत्रिका)। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत शनिवार को भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती विशेष रूप से उपस्थित रहे। नामांकन कार्यक्रम में सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य डॉ. मजीद मलिक कर्मांडो, विधायक ललित मीणा, पूर्व विधायक हेमराज मीणा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष मकसूद खान, मोर्चा पूर्व प्रदेश मंत्री हुसैन पठान, अशाफाक भाई मांगरोल, डॉ. इकबाल खान, छोटू लाल सुमन, हसीन खान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। इस अवसर पर हामिद खान मेवाती ने कहा कि भाजपा की सरकार ने विकास और सेवा के नए मानक स्थापित किए हैं। अंता क्षेत्र में भी भाजपा का परचम एक बार फिर लहराएगा।

देश और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं किसान हित में कार्य- गोपाल शर्मा

-जयपुर के 3 लाख 25 हजार 250 किसानों को 32 करोड़ 52 लाख 50 हजार की राशि हस्तांतरित

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शनिवार धनतेरस के शुभ अवसर पर नदबई भरतपुर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चतुर्थ किश्त की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रति कृषक 1000 राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिला स्तरीय समारोह वी.सी. के माध्यम से जिला परिषद जयपुर के सभागार में आयोजित हुआ। इस दौरान जयपुर जिले के 3 लाख 25 हजार 250 किसानों को 32 करोड़ 52 लाख 50 हजार की राशि

हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर सिविल लाईन्स विधायक डॉ. गोपाल शर्मा ने दीपोत्सव की सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस देश और प्रदेश में किसान हीतैषी सरकारें कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे अपनी समस्याओं से राज्य सरकार को अवगत कराएं ताकि उनका समाधान समय रहते कृषक हित में किया जा सके। इस अवसर पर जिला कलेक्टर जयपुर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर उत्तर मुकेश कुमार मूण्ड सहित अन्य जनप्रतिनिधि व कृषक उपस्थित थे।

आवश्यक नम्बर		रॉयल पत्रिका	
विजली फॉन्ट के लिए		पानी के लिए	
टोल फ्री नंबर	18001806507	जलदाय कार्यालय	2706624
वाट्सएप नंबर	9414037085	फायर ट्रिगेड	2747400
कन्ट्रोल केयर	22030000	मैडिकल इमरजेंसी के लिए	
आईबीआरएस	1912	एंबुलेंस	102/108
कचरा गाड़ी के लिए		एसएमएस इमरजेंसी	2518333
ग्रेटर	2747400	महिला चिकित्सालय	22610616
सीवैज लीकेज	2607500	अनाम शांति	22378721
हेरिटेज	2607500	SDMH	22574189
टोल फ्री नंबर	14420	SMS ब्लॉक वैक	22518222
पुलिस की मदद के लिए		कल्याण ब्लॉक वैक	22721771
साइबर क्राइम	1930/2360094	घायल पशुओं के लिए	
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38	नगर निगम	2747400
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630	बर्ड फीडिंग	9887345580
वाइल्ड डेल्टाइन	1098	हेल्प डन सफरिंग	8107299711
महिला हेल्थलाइन	1090	जनमंत्र ट्रस्ट	7230055800
मुख्यमंत्री पोर्टल	181	पशु चिकित्सालय	2747400

'जश्र-ए-सैयद' में सर सैयद अहमद खान को दी श्रद्धांजलि

-ए.एम.यू. ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन राजस्थान जयपुर द्वारा आयोजन

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। ए.एम.यू. ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन राजस्थान जयपुर की ओर से होटल ग्रैंड इंडियाना में सर सैयद अहमद खान की जयंती के अवसर पर 'जश्र-ए-सैयद' कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कुरआन की तिलावत से हुई, जिसे नईम कुरेशी ने पेश किया। मुख्य अतिथि सय्यद राशिद शमशाद (मुंबई) ने कहा कि 'सर सैयद की शिक्षा और एकता की तहरीक आज भी हमारी राह रोशन करती है।' विशिष्ट अतिथि टी.एस. शर्मा ने कहा कि 'अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने गरीबों और पिछड़ों को शिक्षा के समान अवसर दिए, जिसके लिए हम सदैव आभारी हैं।' महासचिव डॉ. सय्यद अब्दुल मुजीब ने बताया कि संस्था हर साल 12 से 17 अक्टूबर तक 'सर सैयद वीक' के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करती है। इस अवसर पर विजेता छात्र-छात्राओं को मुख्य अतिथि व अध्यक्ष अज़हर एहसन खान ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉ. जलालुद्दीन अंसारी, गज़ाला परवीन, डॉ. महमूद एहसन



सिद्दीकी व डॉ. रफ़ी उल्लाह फारूकी ने सर सैयद के जीवन व योगदान पर विचार रखे। अंत में यूनिवर्सिटी तराना और राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। सभी ने सर सैयद डिनर में भाग लिया।

जिला जयपुर द्वितीय में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन

- गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की हुई जांच, मिला उपचार

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत जिले में शनिवार को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। जिसमें उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका ईलाज करने के साथ पोषण युक्त आहार की जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए वाउचर प्रदान किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मिश्र ने बताया कि शनिवार को जिले के चिकित्सा संस्थानों पर मनाए गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और मां वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी कराने के लिए मां वाउचर प्रदान किए गए। अभियान में गर्भवती महिलाओं के रक्तचाप,



शर्करा के स्तर, वजन, लंबाई, हीमोग्लोबिन, रक्त, एचआईवी जांच, हृदय स्पंदन आदि की जांच कर उनकी गर्भ में पल रहे शिशु और स्वयं की देखभाल के विषय में बताया गया और आई.एफ.ए. कैल्शियम तथा अन्य आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस अवसर पर चिकित्साकर्मियों द्वारा उन्हें पौष्टिक आहार के महत्व को बताते हुए पोषणयुक्त आहार लेने हेतु जागरूक किया गया।

स्व. राव प्रताप सिंह शाहपुरा की पुण्यतिथि पर जनसेवा कार्यक्रमों का आयोजन

शाहपुरा (रॉयल पत्रिका)। शाहपुरा राजपरिवार के स्व. राव प्रताप सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर युवराज दिगराज सिंह शाहपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में दिगराज सिंह शाहपुरा के नेतृत्व में विविध सेवा एवं जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिगराज सिंह शाहपुरा ने स्थानीय अस्पतालों में जाकर मरीजों को फल वितरण किया तथा उनका हालचाल जानकर उन्हें हौसला और शुभकामनाएं दीं। साथ ही गौशालाओं में चारे की व्यवस्था कराई गई, जिससे पशुधन की सेवा का संदेश समाज में जाए। सर्दियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट द्वारा अनाथ, निर्धन एवं सड़क पर रहने वाले



व्यक्तियों को कंबल और गर्म वस्त्र वितरण कर मानवता और संवेदना का संदेश दिया गया। दिगराज सिंह शाहपुरा केवल शाहपुरा राजपरिवार के सदस्य ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील समाजसेवी और जनसेवक युवा

नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। वे राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुनना और समाधान के लिए प्रयास करना अपना कर्तव्य मानते हैं। इस अवसर पर दिगराज सिंह शाहपुरा जी ने कहा कि 'हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके द्वारा दिखाए गए सेवा और मानवता के मार्ग पर चलें और समाज के हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाएँ।' उनकी कार्यशैली और विनम्र व्यक्तित्व ने उन्हें शाहपुरा ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में एक प्रेरणा-स्रोत युवा नेता के रूप में स्थापित किया है। वे सेवा, संस्कार और समर्पण के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री ने धनतेरस के अवसर पर किसान सम्मान निधि राशि हस्तांतरित कर दी सौगात

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धनतेरस के शुभ अवसर पर प्रदेश के 70 लाख से अधिक किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 718 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर पांच दिवसीय पर्व दीपावली पर किसानों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने शनिवार को नदबई भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से किसान सम्मान निधि योजना की चतुर्थ किश्त का हस्तांतरण कर किसानों को दीपावली पर्व पर सम्मान के साथ सौगात प्रदान की। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित वी सी रूम में किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में राज्य मंत्री विजय



सिंह चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को किए गए वादे को निभाते हुए बढ़ती कर ₹3000 रुपये राशि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से भी दिया जा रहा है इस

अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से प्रसारण किया गया जिसको सभी अधिकारियों एवं उपस्थित किसानों ने सुना। इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलक्टर डॉ महेंद्र खड्गवात, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती ऋचा तोमर सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

धन तेरस भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए समर्पित है - डी के सोनी

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। भामाशाह डी के सोनी ने कहा कि धन तेरस दिवाली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए समर्पित है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता हैं। लोग नए बर्तन, सोना-चांदी खरीदते हैं और घरों में दीये जलाते हैं। सोनी ने परंपराओं का महत्व बताया कि कथाओं के

कारण, लोग धनतेरस पर आरोग्य और समृद्धि की कामना करते हैं। **बर्तन खरीदना:** समृद्ध मंधन से अमृत कलश के प्रकट होने के कारण इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। **सोना-चांदी खरीदना:** धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में सोना और चांदी जैसी शुभ धातुएं खरीदी जाती हैं।

यम दीपदान: मृत्यु के भय से मुक्ति पाने और परिवार की लंबी आयु की कामना के लिए घर के बाहर दीपक जलाया जाता है।



एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन

-खेती के संबंध में नवीनतम तकनीकी की दी जानकारी

झुंझुनू (रॉयल पत्रिका)। आत्मा कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को रबी मौसम पूर्व की एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें झुंझुनू पंचायत समिति के समसपुर, प्रतापपुरा, काली पहाड़ी, भड़ोन्दा खुर्द, इण्डाली, भेड़ा की दाणी, बाकरा, बुडाना, आबूसर सहित विभिन्न गांवों के 100 कृषकों ने भाग लिया। गोष्ठी में पूर्व क्षेत्रीय निदेशक डॉ. सहदेव सिंह ने खेत की तैयारी से ही अच्छा प्रबंधन करने, फसल चक्र भूमि व बीजोपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा) झुंझुनू शीशाराम जाखड़ ने वर्षा जल का उचित प्रबंधन, कुशलतम उपयोग, खेती में नवाचार, फसल विविधकरण व सिंचाई की नवीनतम पद्धतियाँ अपनाकर कम पानी में अधिक पैदावार लेने के बारे में जानकारी दी। कृषि विज्ञान केन्द्र आबूसर के मुख्य वैज्ञानिक एवं समन्वयक डॉ. दयानन्द सिंह ने रबी फसलों की जिले के लिए उपयुक्त उन्नतशील



व प्रमाणित किस्में, सन्तुलित उर्वरक प्रयोग, फसलों में कान्तिक अवस्थाओं पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण का उचित समय व रोग कीटों की रोकथाम के बारे में विस्तार से चर्चा की। (आत्मा) उप परियोजना निदेशक प्रमोद कुमार ने आत्मा योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण व कृषक पुरस्कार के बारे में जानकारी दी। एग्री क्लीनीक झुंझुनू के कृषि अनुसंधान अधिकारी अनुपम महर्षि ने मिट्टी व पानी की जांच व फसलों के लिए आवश्यक पौषक तत्वों के बारे में बताया। झुंझुनू बी.टी.टी. कन्वेनर एवं सहायक कृषि अधिकारी डॉ. राकेश कटवा ने कृषि विभाग

की अनुदानित योजनाओं की जानकारी दी गोष्ठी के समापन पर प्रश्रोतरी कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कम्पश प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कृषक गोतम मीणा खतेहपुरा, प्रवीण कुमार शर्मा इण्डाली श्यामसुन्दर मीणा खतेहपुरा को इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जीएसएस खजपुर नया के अध्यक्ष हरिसिंह महला, कृषि पर्यवेक्षक आबूसर जगदीश खीचड़, कृषि पर्यवेक्षक खजपुर नया पंकज कुल्हरी, उद्यान विभाग के चतरसिंह भालोठिया, तपेश कुमार, नितेश कुमार सहित विभिन्न गांवों के कृषक मित्र व प्रगतिशील कृषक भी उपस्थित थे।

मंत्री कुमावत ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण

-शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों से मिला आमजन को लाभ, शिविरों का निरीक्षण किया

पाली (रॉयल पत्रिका)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूलमंत्र से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रारम्भ किए गए शहरी सेवा शिविर-2025 जनसेवा का पर्याय बन रहे हैं। 17 सितम्बर से प्रारम्भ हुए इन शिविरों में अब तक हजारों की संख्या में आमजन के प्रकरणों का निस्तारण कर त्वरित राहत पहुंचाई गई है साथ ही ग्रामीण सेवा शिविरों में भी आमजन के कई काम निपटाए जा रहे हैं। प्रदेशभर में 17 सितम्बर से संचालित हुए ये शिविर जनता की उम्मीदों को हकीकत में बदल रहे हैं। आमजन के लिखित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अधिकृत सेवा और सुविधा के लिए इंतज़ार न करना पड़े, यह इन शिविरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।



निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कुमावत ने 15 वे वित्त आयोग योजनान्तर्गत स्वीकृत 4.25 लाख रुपए की लागत से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में निर्मित सी सी ब्लॉक रोड, महा नरेगा में स्वीकृत राशि से सी सी रोड व नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण किया।

बामनेरा में इन कार्यों का भी कृषि लोकार्पण, शिविर का निरीक्षण किया-

मंत्री कुमावत ने ग्राम पंचायत बामनेरा में आयोजित ग्राम सेवा शिविर का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में नाबाईद द्वारा संचालित

योजना आरआईडीएफ के अंतर्गत 75 लाख रुपए की लागत से बनी 3 किलोमीटर लंबी मिसिंग लिंक सड़क का लोकार्पण भी किया। यह सड़क बमनेरा से पोयना तक बनाई गई है। साथ ही मंत्री कुमावत ने बमनेरा में ही राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस भवन के लिए राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत हुई है। इस मौके परपूनम सिंह, हडमत सिंह, लाला राम देवासी, एसडीएम कालूराम कुम्हार, तहसीलदार दिनेश आचार्य, भरत सिंह राजपुरोहित पालडी जोड़, प्रधान प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह, बामनेरा सरपंच रमणीक त्रिवेदी आदि मौजूद रहे।

धनतेरस पर किसानों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का तोहफा

-पाली जिले के किसानों को मिली सीएम किसान सम्मान निधि की किस्त - एक लाख 68310 किसानों के खातों में 16 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपये ट्रांसफर

-पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम

मोहम्मद यासीन
पाली (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारे राष्ट्र निर्माता और भारत की आत्मा हैं। कृषक जब अपने खेतों में दिन-रात मेहनत करता है, तभी हमारी थाली में भोजन आ पाता है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता शब्द समाज में किसान के सम्मान, गरिमा और महत्व को दर्शाता है। हमारा किसान समृद्ध होगा तो देश और प्रदेश भी विकसित होगा, इसलिए राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। शर्मा ने शनिवार को भरतपुर के नदबई में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्य के लगभग 72 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में लगभग 718 करोड़ रुपये की राशि का हस्तान्तरण किया। इसी कड़ी में पाली जिले का जिला स्तरीय समारोह जिला परिषद सभागार में पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान जिलेभर से पहुंचे सैंकड़ों किसान जुड़ते। मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली जिले के



एक लाख 68 हजार किसानों के खातों में चौथी किस्त के रूप में कुल 16 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस जिला स्तरीय समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को सर्वोपरि मानते हुए उनके कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ की। राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पौने दो साल में किसानों को 7 हजार 31 करोड़ रुपये से अधिक दिए जा चुके हैं। कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार के अतिरिक्त 3 हजार की राशि अलग से प्रदेश के किसानों को देती है। इसके तहत अब तक 70 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 355 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की

गई है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 8,386 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है जो एक रिकॉर्ड है। इसी क्रम में चौथी किस्त के रूप में पाली जिले के एक लाख 68310 किसानों को 16 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपये किसानों को और दिए गए हैं। कार्यक्रम में पाली विधायक भीमराज भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी, पंचायत समिति प्रधान मोहिनी देवी, प्रधान प्रतिनिधि पुषराज पटेल, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि भंवर चौधरी, पूर्व उप जिला प्रमुख नवल किशोर शर्मा, सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक प्रबंध निदेशक प्रशांत कल्ला, एडीएम बजरंग सिंह, जिला परिषद के सीईओ मुकेश चौधरी, सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में किसान व आमजन उपस्थित रहे।

त्रिनेत्र बालगृह, राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह तथा मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का निरीक्षण कर जांची व्यवस्थाएं

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम ने त्रिनेत्र बालगृह तथा राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह सवाई माधोपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने त्रिनेत्र बालगृह के सचिव हरीश उपाध्याय तथा राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह के अधीक्षक विमलेश कुमार से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के अन्तर्गत संस्था की भौतिक संरचना, संस्था में रसोईघर, प्राथमिक उपचार कक्ष, भोजन कक्ष, भंडारगृह, मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय, शौचालय, स्नानघर, परामर्श मार्गदर्शन कक्ष, कार्यालय कक्ष, खेल मैदान आदि की उपलब्धता, सईयों में परिसर को गर्म रखने के लिए हीटर की व्यवस्था, मोसमानुकूल इंतजामों, संस्था में प्राथमिक उपचार किट, अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था, ओढ़ने-बिछाने के लिए कंबल, रजार्ड, षाई, दरी की उपलब्धता, मच्छरदानी की व्यवस्था, संस्थान की साफ-सफाई, बालकों की



दिनचर्या, शारीरिक व्यायाम, योग, शैक्षणिक क्लासेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन और खेल, बालकों को संतुलित आहार, नाश्ते व भोजन की उपलब्धता, चिकित्सकीय सुविधा, डॉक्टर की नियमित विजिट, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता, बालकों को शिक्षा के उपलब्ध अवसर, बालकों को उनकी आयु, अभिरुचि और योग्यता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण, बालकों के लिए मनोरंजक सुविधाओं जैसे खेल, योग, टेलीविजन, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संस्था के प्रबंधन व प्रत्येक बालक की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए प्रबंधन समिति की मीटिंग आदि के संबंध में जानकारी ली गई।

साथ ही मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह सवाई माधोपुर का निरीक्षण कर केयरटेकर मनीष पंडित से संस्था में स्टाफ की स्थिति, संस्था में आवासीय महिला एवं पुरुषों की संख्या, उन्हें भोजन, पेयजल एवं चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, डॉक्टर की विजिट, संस्था की साफ-सफाई, संस्था में आने वाले लोगों का रिकॉर्ड, परिजनों से बातचीत आदि के संबंध में जानकारी ली गई। केयरटेकर मनीष पंडित ने बताया कि संस्था में लोगों की स्वास्थ्य जांच हेतु डॉक्टर की विजिट नहीं होती है, किसी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे राजकीय सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर में उपचार हेतु ले जाया जाता है।

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26

-जिले में 31 सड़कों के सुदृढीकरण के लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत -मंत्री डॉ. मीणा के प्रयासों से क्षेत्र में 40 किलोमीटर लम्बी सड़कों का विकास होगा

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। कृषि, उद्यानिकी, ग्रामीण विकास एवं आपदा प्रबंधन विभागों के मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के प्रयासों से सवाई माधोपुर जिला लगातार विकास कार्यों में अग्रणी है। इस क्रम में राज्य सरकार ने जिले में 31 सड़कों के सुदृढीकरण एवं मरम्मत के लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। भेरू दरवाजा स्थित राधाकृष्ण गौशाला पर आयोजित होने वाली अमृतमयी श्रीमद्भागवत का समापन अवसर, 3 नवम्बर 2025 को मंत्री डॉ. मीणा द्वारा इन सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के अनुसार, बजट घोषणा 2025-26 के तहत सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 90 करोड़ रुपये की इस राशि से करीब 40 किलोमीटर लम्बाई की विभिन्न सड़कों के सुदृढीकरण, चौड़ाईकरण, सौन्दर्यकरण और निर्माण कार्य किए जाएंगे। बीते सप्ताह प्राप्त हुई स्वीकृति के क्रम



में हमीर सर्किल से आलनपुर सर्किल के बीच 15 करोड़ रुपये से सड़क निर्माण और स्टेट हाईवे-122 पर 6 किलोमीटर लम्बाई की सड़क पर 6 करोड़ रुपये खर्च कर चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण किया जाएगा। साथ ही, जड़ावता और खाटकलां शमशान घाट, हाउसिंग बोर्ड और श्यामपुरा बस स्टैण्ड, सर्किट हाउस रोड तथा सामान्य चिकित्सालय आदि के आस-पास की गलियों और कॉलोनीयों में सड़कों के विकास पर लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार, हाउसिंग

बोर्ड और मीणा कॉलोनी की अतिरिक्त सड़कों के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये तथा रणथम्भौर रेलवे स्टेशन, पॉलिटेक्निक कॉलेज, लटिया नाले, रणथम्भौर रोड आदि क्षेत्रों में लगभग 16 किलोमीटर लम्बाई के सड़क विकास के कुल 13 निर्माण कार्यों पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिला मुख्यालय के बजरिया क्षेत्र में भी 7 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की 4 लेन की सड़क निर्माण के कार्य में लगभग 35 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

किसान सम्मान निधि का डीबीटी अन्तःकरण -जिलेभर के किसानों के खातों में आएँ 24.29 करोड़ रुपए

झुंझुनू (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभार्थियों को चतुर्थ किस्त अन्तरण के क्रम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम नदबई भरतपुर में आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसानों के खातों में योजनान्तर्गत चतुर्थ किस्त राशि का 1 हजार रुपए का अन्तरण डीबीटी के माध्यम से किया गया। इस दौरान इस योजना में पूरे राज्य में 71.80 लाख किसानों के खातों में राशि रूपये 717.97 करोड़ तथा जिले में 2,42,937 कृषकों के खातों में राशि रूपये 24.29 करोड़ रुपए का अन्तरण हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला सूचना केन्द्र के सभागार कक्ष में शनिवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि योजना, राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना



आदि की जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम के दौरान झुंझुनू विधायक राजेंद्र भाबू प्यारेलाल दूकिया, महेन्द्र चन्दवा तथा अन्य जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सीसीबी एमडी सदीप शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा किसान कल्याण योजनान्तर्गत राशि रूपये 5.00 लाख, कृषक मित्र ऋण योजनान्तर्गत राशि रूपये 3.00 लाख तथा गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजनान्तर्गत 11 आवेदकों को राशि रूपये 11.00 लाख का ऋण वितरण किया गया।

कार्यक्रम के दौरान भूमि विकास बैंक सचिव दीपेन्द्र सिंह शेखावत, झुंझुनू केवीएसएस प्रबंधक रामरत्न डोई, बैंक के अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी रंजना स्वामी, मुख्य प्रबंधक सत्यवीर सिंह मुख्य प्रबंधक बैंक, हनुमान प्रसाद खाती, जितेंद्र कुमार, लोकेन्द्र सिंह राठौड़, सदीप कुमार, मनीष पंवार, सहकारिता निरीक्षक अविनाश महला एवं योजनान्तर्गत विभिन्न लाभार्थियों सहित 250 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

रबी फसल 2025-26 के लिए भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में सिंचाई पानी वितरण हेतु रेगुलेशन कमेटी की बैठक आयोजित

हनुमानगढ़ (रॉयल पत्रिका)। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को भाखड़ा सिंचाई प्रणाली (सादुल एवं करणी सिंह ब्रांच) की जल वितरण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का उद्देश्य आगामी रबी फसल 2025-26 के लिए सिंचाई पानी वितरण की रूपरेखा तय करना रहा। बैठक में सदस्यों ने विभागीय प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और सरसों व चने की बुवाई तथा कोर सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी देने की मांग रखी। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सादुल ब्रांच को मौका स्थिति व पानी उपलब्धता के अनुसार पूर्ण क्षमता से चलाया जाएगा। साथ ही, पीबीएन और एलजीडब्ल्यू वितरिका को समान रूप से बैलेंस पानी आवंटित करने का निर्णय लिया गया ताकि एक ही वितरिका की पुनरावृत्ति न हो। बैठक की शुरुआत में रेगुलेशन वृत्त हनुमानगढ़ अधीक्षण अभियंता रामाकिशन ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि भाखड़ा ब्रांच में डिप्लीशन अवधि 21 सितंबर, 2025 से 20 मई, 2026

के दौरान सतलुज नदी के पानी में राजस्थान के हिस्से के रूप में 1,88,725 क्यूसेक डेज तथा रावी-ब्यास नदियों के अधिशेष पानी में से 38,939 क्यूसेक डेज, इस प्रकार कुल 2,27,664 क्यूसेक डेज पानी उपलब्ध होने की संभावना है। यह पानी ड्राई ईयर इन्फ्लो के आधार पर अनुमानित किया गया है, और वास्तविक आवक अधिक रहने पर अनुपातिक वृद्धि की जाएगी। विभागीय प्रस्ताव के अनुसार 21 सितंबर 2025 से 24 मार्च, 2026 तक 1200 क्यूसेक पानी लगातार चलाया जाएगा। इसके पश्चात 24 मार्च से 20 अप्रैल, 2026 तक नहर बंदी रहेगी, जबकि 20 अप्रैल से 20 मई, 2026 तक पेयजल हेतु 600 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार कुल 2,37,600 क्यूसेक डेज पानी आवश्यक होगा, जो उपलब्धता से 9,936 क्यूसेक डेज अधिक है। इस कमी की पूर्ति डिप्लीशन अवधि में लगभग 13.62 प्रतिशत अधिक वास्तविक आवक होने पर संभव होगी।

गीतांजली हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल आयोजित



उदयपुर (रॉयल पत्रिका)। गीतांजली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अग्निशमन विभाग, नगर निगम उदयपुर के सहयोग से फायर सेफ्टी ट्रेनिंग एवं मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य हॉस्पिटल परिसर में आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना था। कार्यक्रम में फायर सेफ्टी अधिकारियों ने हॉस्पिटल स्टाफ को आग लगने की स्थिति में तुरंत उठाए जाने वाले कदमों, सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग तथा रोगियों और स्टाफ की सुरक्षित निकासी के तरीकों की जानकारी दी। इस

अवसर पर गीतांजली यूनिवर्सिटी के वाईस प्रेसिडेंट सदीप कुणावत, गीतांजली हॉस्पिटल के सीईओ ऋषि कपूर, गीतांजली हॉस्पिटल के जीएम ऑपरेशन अमित बंसल, सीएसओ चक्रपाल सिंह ने बताया कि नियमित अंतराल पर ऐसे अभ्यास से न केवल सुरक्षा स्तर बढ़ता है बल्कि स्टाफ की सतर्कता और तत्परता भी सुनिश्चित होती है। हॉस्पिटल प्रशासन ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भविष्य में भी ऐसे सुरक्षा प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे।

अमृता हाट का हुआ विधिवत समापन -झुंझुनू विधायक रहे मुख्य अतिथि



झुंझुनू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय के शहीद परमवीर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल प्रांगण में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चल रहे अमृता हाट का शनिवार को विधिवत समापन किया गया। विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि झुंझुनू विधायक राजेंद्र भाबू रहे। समापन समारोह में समाजसेवी प्यारेलाल दूकिया, मुख्य लेखा अधिकारी निदेशालय पशुपालन विभाग दीपिका सोह, अतिरिक्त कोषाधिकारी प्रियंका लांबा, अतिरिक्त कोषाधिकारी प्रेरणा कालेर, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नेहा झाझडिया, समाजसेवी कमलकांत शर्मा, लोकेश अग्रवाल, उपनिदेशक कृषि शीशाराम जाखड़ अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मेले में सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह के रूप में सरस्वती एसएचजी झालावाड़, रामदेव एसएचजी बाड़मेर, श्याम जी एसएचजी किठना, मां दुर्गा

एसएचजी बूंदी, छवि एसएचजी किशनगढ़ को सम्मानित किया गया। वहीं मेले में सहयोग करने पर अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि मेले के समापन समारोह में झुंझुनू विधायक राजेंद्र भाबू द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान के तहत राजीविका विभाग द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एटिंगा गाड़ी को टैक्सी सर्विस के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मेले के समापन के दौरान नगर परिषद के सहायक अभियंता लोकेश दुलड, कार्यवाहक एसआई सदीप कुमार, स्कूल प्राचार्य आशा नीलू, उप प्राचार्य जमना झाझरिया, टी एसएस अग्रवाल, उपनिदेशक कृषि शीशाराम जाखड़ अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मेले में सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह के रूप में सरस्वती एसएचजी झालावाड़, रामदेव एसएचजी बाड़मेर, श्याम जी एसएचजी किठना, मां दुर्गा

धनतेरस पर जिले के 2.06 लाख किसानों को 20.64 करोड़ रुपये की सौगात

-सिविल लाइन के सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम



हनुमानगढ़ (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चतुर्थ किस्त का हस्तांतरण शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया गया। भरतपुर जिले के नदबई में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का जिला स्तरीय आयोजन सिविल लाइन स्थित सामुदायिक भवन, जंक्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के 2,06,378 किसानों के खातों में 20.64 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी माध्यम से सीधे हस्तांतरित की। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेजू ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को खेती-किसानी में सहायता मिल रहा है। जनप्रतिनिधि अमित सहू ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की प्राथमिकता है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता और

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत प्रतिवर्ष 3 हजार रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद डेजू, जनप्रतिनिधि अमित सहू, हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन राजेंद्र न्योल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उममेदीलाल मीना, जिला परिषद सीईओ ओ.पी. बिश्रोई, उपखंड अधिकारी मांगीलाल सुथार तथा हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक नरेश शुक्ला, मुख्य प्रबंधक संजय शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी राजेंद्र लदोईया, वरिष्ठ प्रबंधक अनिल बिश्रोई, परमानराम मायल, मुकेशचंद बैरवा, शैलेन्द्र गुप्ता सहित जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक, सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान लाभार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मंच संचालन भीष्म कौशिक ने किया। उपस्थित किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि रबी फसल की तैयारी में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

अजमेर के बहुप्रत्याशित सिंह द्वार निर्माण कार्य का हुआ भव्य शुभारंभ

-अजमेर की पहचान बनेगा यह द्वार- देवनाजी

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। अजमेर शहर की सौंदर्यता और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊँचाई देने के उद्देश्य से जयपुर रोड स्थित अशोक उद्यान के सामने सिंह द्वार प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाजी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी और जल एवं पेयजल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के कर कमलों द्वारा प्रवेश द्वार निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। यह द्वार लगभग 250 लाख रुपये की लागत से भव्य रूप में बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाजी ने कहा कि जब मैं अन्य बड़े शहरों में प्रवेश करता था तो वहां का भव्य प्रवेश द्वार उस शहर की पहचान बयान करता दिखाई पड़ता था। मेरे मन में यह विचार था कि अजमेर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी में भी एक प्रतीकात्मक प्रवेश द्वार होना चाहिए जो आगतुकों का स्वागत करे और शहर की गरिमा बढ़ाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में इस



कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रवेशद्वार अजमेर के विकास की दिशा में एक मील का पथर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सिंह द्वार की चौड़ाई लगभग 35 मीटर एवं ऊँचाई लगभग 20 मीटर होगी। इसमें जयपुर-अजमेर मार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों के लिए 3-3 लेन कुल 6 लेन की व्यवस्था होगी। साथ ही दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़े फूटपाथ रखे जाएंगे। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ 13-13 मीटर के दो क्लिप स्तूप स्थापित होंगे। ये संरचना को सुदृढ़ता और भव्यता प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रवेश द्वार के निर्माण में जोधपुर के सूरसागर पथर का उपयोग किया जा रहा

है। इसमें गुम्बद, नक्काशी और फसाड लाइटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का समावेश करते हुए इसे सांस्कृतिक और स्थापत्य दृष्टि से आकर्षक रूप दिया जाएगा। देवनाजी ने कहा कि अजमेर के विकास को गति देने के लिए एक माकडवाली क्षेत्र में आईटी पार्क, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक पेयजल के लिए तीन नए रिजर्वायर जल की पर्याप्त उपलब्धता, निर्बाध विदुत् आपूर्ति के लिए जीएसएस निर्माण और रेलवे स्टेशन के उन्नयन जैसे अनेक कार्य तेजी से शहर के विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित

-जिला कलक्टर ने जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा कर दिए

आवश्यक निर्देश

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति की स्थिति तथा स्वच्छता से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने कहा कि जलजीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन का लक्ष्य प्राथमिकता से पूरा किया जाए। उन्होंने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को कनेक्शन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। इससे अधिक से अधिक परिवारों तक समय पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही ऐसे कार्य जिनके कार्यदिश जारी हो चुके हैं उन कार्यों को तुरंत प्रारंभ करने को निर्देशित किया। लोक बन्धु ने पाइपलाइन



बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की समयबद्ध मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा भौतिक जांच की जाएगी। पाइपलाइन मरम्मत एवं सड़क पुनर्निर्माण से संबंधित कार्यों की सूची जिला प्रशासन को प्रेषित की जाए। पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित विभागों और उपयोगकर्ता संस्थाओं को सौंपने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। जिला कलक्टर ने आने वाले गर्मियों के मौसम को

ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को अभी से समर कंटिन्जेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने दीपावली के दौरान निरंतर एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्कता बरतें और किसी भी प्रकार की शिकायत का त्वरित निस्तारण करें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर वंदना खोरवाल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

श्री पुष्कर मेला 2025 कार्यक्रमों के फोल्डर का किया गया विमोचन

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। श्री पुष्कर मेला 2025 के कार्यक्रमों के फोल्डर का शुक्रवार को जिला कलक्टर लोक बन्धु, पुलिस अधीक्षक वन्दिता राणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश द्वारा विमोचन किया गया। जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि श्री पुष्कर मेला 30 अक्टूबर से आरम्भ होगा। यह मेला 5 नवम्बर तक चलेगा। इस दौरान जिला प्रशासन, पशु पालन विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के फोल्डर का विमोचन किया गया। गुरुवार को 30 अक्टूबर को मेला मैदान में प्रातः 10 बजे पूजा, ध्वजारोहण एवं नगाड़ा वादन के साथ मेले का शुभारम्भ होगा। इसके पश्चात स्कूली छात्राओं द्वारा मांडना प्रतियोगिता और समूह नृत्य का आयोजन किया जाएगा। चक दे राजस्थान फुटबॉल मैच स्थानीय बनाम विदेशियों के मध्य होगा। सायं 6 बजे पुष्कर सरोवर घाट



पर दीपदान तथा रंगोली होगी। सायं 6.30 बजे पुष्कर की महाआरती, पुष्कर सरोवर घाटों पर अभिषेक तथा मेला मैदान मंच में पुष्कर की आवाज के अंतर्गत स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। सायं 7 बजे हास्य कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ डब्ल्यूजेडसीसी और राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा मेला मैदान में प्रस्तुत होगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार 31 अक्टूबर को मेला मैदान में प्रातः 10 बजे से लंगड़ी टांग, सतोलिया और गिल्ली डंडा के खेल स्थानीय बनाम विदेशियों के मध्य होंगे। साथ ही उष्ट्र श्रृंगार प्रतियोगिता तथा उष्ट्र नृत्य प्रतियोगिता भी

होगी। मेला मैदान मंच पर सायं 6.30 बजे पुष्कर की आवाज में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों के पश्चात एनजेडसीसी और कुटले खान परियोजना द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी। उन्होंने बताया कि शनिवार एक नवम्बर को मेला मैदान में प्रातः 10 बजे कबड्डी मैच स्थानीय बनाम विदेशी रहेगा। अश्व नृत्य प्रतियोगिता के पश्चात अंतरपंचायत समिति ग्रामीण खेल में रस्सा कस्सी, वॉलीबॉल एवं कबड्डी के खेल होंगे। मेला मैदान मंच में सायं 6.30 बजे पुष्कर की आवाज स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियों के बाद सुरस बैंड और नीरज आर्य के कबीर केफे द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जाएगी।

पंच गौरव से जिले को मिलेगी नई पहचान

चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। जिला स्तरीय पंच गौरव कार्यक्रम समिति की त्रैमासिक (तृतीय) बैठक बुधवार को प्रातः 11 बजे कलक्ट्रेट परिसर स्थित समिति कक्ष में जिला कलक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई तथा आगे की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।

जिले के पंच गौरव तत्वों के विकास पर जोर-

बैठक में जिला कलक्टर आलोक रंजन ने जिले में पंच गौरव

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रोत्साहन एवं प्राप्त बजट का उपयोग पंच गौरव गाइडलाइन के अनुसार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के पंच गौरव तत्व - एक जिला एक उपज सीताफल, एक जिला एक वनस्पतिक प्रजाति बेलपत्र, एक जिला एक उत्पाद ग्रेनाइट एवं मार्बल, एक जिला एक पर्यटन स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग और एक जिला एक खेल कबड्डी के विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए ताकि जिले को विशिष्ट पहचान मिल सके।

सीताफल और पर्यटन विकास को मिले बढ़ावा-

जिला कलक्टर ने उद्यान विभाग को सीताफल के उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने, इसके जैविक उत्पादों को जी.आई. टैग दिलाने तथा "Chittorgarh Fort Organic Sitaफल" नाम से ब्रांडिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था करने की बात कही।

जिला स्तरीय युवा महोत्सव की तैयारियों की बैठक आयोजित

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजन समिति की बैठक शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर वन्दना खोरवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला कलक्टर वन्दना खोरवाल ने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजन समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें आयोजन की तैयारियों के सम्बन्ध में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय युवा महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इनमें डिक्लेमेशन, कहानी लेखन, चित्रकारी, लोक नृत्य, एकल लोक नृत्य, लोक गीत, एकल लोक गीत, शायरी लेखन, अभिनय विज्ञान मेले की प्रदर्शनी, हस्तशिल्प, कपड़ा, कृषि उत्पाद प्रमुख है। साथ ही राजस्थान की लुप्त कला जैसे फड़, रावणहस्ता, रम्मत्, अलगोजा, माण्डणा, लांचामांगणीहार, कठपुतली, खडताल, मोरचंग, भंगम आदि आयोजित की जाएगी। भारत सरकार की गाईड लाईन के



अनुसार 15-29 आयु वर्ग के युवाओं को राजस्थान युवा बोर्ड पोर्टल एवं माय भारत पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि युवा महोत्सव का आयोजन चार स्तरों पर होगा। सबसे पहले एक दिवसीय जिला स्तर युवा महोत्सव होगा। एक दिवसीय संभाग स्तर युवा महोत्सव में जिला स्तर के विजेता दल भाग लेंगे। तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में संभाग स्तरीय विजेता दल भाग लेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राज्य में चयनित विजेता दल को वरीयता दी जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा विजेताओं के लिए राज्य सरकार

द्वारा अनुशंषा की जाएगी। उन्होंने बताया कि महोत्सव में एकल एवं सामूहिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक सदस्य को जिला स्तर पर एक-एक हजार एवं संभाग स्तर पर 1500-1500 रूपये दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान वालों को 50-50 हजार रूपये, द्वितीय स्थान वालों को 25-25 हजार रूपये तथा तृतीय स्थान वालों को 10-10 हजार रूपये के पुरस्कार राजस्थान कला-रत्न लोगों सहित स्मृति चिन्ह पुरस्कार, प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा

शिविर में आपसी सहमति से खाता विभाजन की सुविधा मिली

-काशतकारों ने जताया माननीय मुख्यमंत्री का आभार

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिले में आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में आमजन की समस्याओं का समाधान हो रहा है। साथ ही उन्हें केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का मौके पर ही लाभ मिल रहा है। राहत मिलने पर लाभार्थियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार का आभार जताया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने हेतु ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025 के अंतर्गत शिविर का आयोजन शुक्रवार को ग्राम पंचायत 3 सी छोटी पंचायत समिति श्रीगंगानगर में किया गया। शिविर में कविता पत्नी रणवीर, गुलाबी देवी पत्नी रामप्रताप, सुमन, पूतम पुत्रियां रामप्रताप, रणवीर पुत्र रामप्रताप, रामकुमार पुत्र रावता राम निवासी मिर्जेवाला ने शिविर में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि उनकी कृषि भूमि चक 3के के संयुक्त खाता 75/48 में मुरुब्बा नंबर 42,44, 45



में कुल रकबा 12.9030 हेक्टेयर नहरी मय खाला दर्ज रिकॉर्ड है। सहकाशतकारों ने काशत की सुविधा, बैंक से ऋण प्राप्त करने एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आपसी सहमति से खाता का विभाजन करवाने का आवेदन किया। शिविर प्रभारी आदराम नायक नायब तहसीलदार मिर्जेवाला ने प्रार्थना पत्र पर पटवारी हलका से रिपोर्ट प्राप्त की गई। समस्त सह काशतकारों के सहमति बयान दर्ज किए गए। शिविर में ही खाता विभाजन आदेश जारी कर पटवारी हलका को पालनार्थ भेजा और एक प्रति काशतकारों को प्रदान की।

शिविर में तीन आवेदन इंद्रसेन पुत्र हरौराम एवं कुलजिन्द्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह सिंह ने रिकॉर्ड में बैंक नाम दुरुस्ती तथा किरण कौर पत्नी दिलबाग सिंह निवासी 5 सी ने खरीद शूदा रकबा हिस्सा की त्रुटि सही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। प्रार्थना पत्रों पर संबंधित पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त प्रकरणों में शिविर में दुरुस्ती के आदेश जारी कर संबंधित पटवारी हलका को पालनार्थ भिजवाये गये। इसके साथ किसानों को लघु कृषक के प्रमाण पत्र जारी किए गए। दस नामांतरण प्रकरणों में निर्णय किया गया।

“हमारी पहल” अभियान का शुभारंभ, युवा नेतृत्व क्षमता निर्माण कार्यशाला का हुआ आयोजन

बूंदी (रॉयल पत्रिका)। बाल विवाह, शीघ्र एवं जबरन विवाह (CEFM) की रोकथाम में युवाओं की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने और बालिकाओं के शिक्षा के अधिकार को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने “हमारी पहल” अभियान का शुभारंभ किया है। अभियान के तहत 16 और 17 अक्टूबर को दो दिवसीय युवा नेतृत्व क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक सीताराम शर्मा ने अभियान की रणनीतियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि “हमारी पहल” अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना भी है। इनमें कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, निःशुल्क



साइकिल वितरण योजना और प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल हैं, जो बालिकाओं को शिक्षा से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण हैं। कार्यशाला के समापन सत्र में युवाओं ने “युवा कहें शिक्षा को हाँ, बाल विवाह को ना” के संदेश को अपने-अपने समुदायों, विद्यालयों और पंचायतों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। युवाओं ने प्रण लिया कि वे रचनात्मक माध्यमों, जनसंवादों और स्थानीय पहलों के ज़रिए बाल विवाह उन्मूलन और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे। यह पहल गर्ल्स

नॉट ब्राइड्स - राजस्थान स्टेट पार्टनरशिप (GNB RJSP) के अंतर्गत कल्प (Centre for Un-folding Learning Potentials) द्वारा समन्वित की जा रही है, जो प्रदेश के 16 जिलों में साझेदार संस्थाओं के सहयोग से लैंगिक समानता और बाल विवाह समाप्ति के लिए कार्यरत है। कार्यशाला का संचालन गर्ल्स नॉट ब्राइड्स राजस्थान के उपाध्यक्ष शिवजी राम यादव, जिला समन्वयक सीताराम शर्मा, गर्ल्स नॉट ब्राइड्स राजस्थान के राज्य सचिवालय (कल्प) के राजन एवं पूतम जोनवाल ने किया।

दीपावली पर बीएसएनएल ने की “दिवाली बोनान्ज़ा ऑफ़र” की घोषणा

बूंदी (रॉयल पत्रिका)। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने दीपावली के अवसर पर अपने उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष “दिवाली बोनान्ज़ा ऑफ़र” की घोषणा की है। यह ऑफ़र पूरी तरह स्वदेशी 4जी मोबाइल सेवा के तहत लॉन्च किया गया है और 15 नवंबर 2025 तक सीमित अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा। इस विशेष योजना के तहत नए मोबाइल कनेक्शन लेने वाले एवं अन्य नेटवर्क से बीएसएनएल में पोर्ट करने वाले ग्राहक मात्र 1 रूपए में 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रतिदिन 2 जीबी हाई-स्पीड डेटा तथा 100 एसएमएस प्रतिदिन की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। बीएसएनएल संचालन क्षेत्र बूंदी के उप महाप्रबंधक जे. पी. मीणा ने बताया कि यह ऑफ़र बीएसएनएल की स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4जी सेवा के प्रति उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इच्छुक उपभोक्ता अपने नजदीकी बीएसएनएल कार्यालय, उपभोक्ता सेवा केंद्र अथवा अधिकृत रिटेलर से नया सिम प्राप्त कर सकते हैं या अपने वर्तमान मोबाइल नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करवा सकते हैं। उप महाप्रबंधक ने बताया कि यह ऑफ़र 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा। बीएसएनएल का यह कदम देशभर में डिजिटल कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने और उपभोक्ताओं को किरफायती दरों पर बेहतर 4जी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।

नॉट ब्राइड्स - राजस्थान स्टेट पार्टनरशिप (GNB RJSP) के अंतर्गत कल्प (Centre for Un-folding Learning Potentials) द्वारा समन्वित की जा रही है, जो प्रदेश के 16 जिलों में साझेदार संस्थाओं के सहयोग से लैंगिक समानता और बाल विवाह समाप्ति के लिए कार्यरत है। कार्यशाला का संचालन गर्ल्स नॉट ब्राइड्स राजस्थान के उपाध्यक्ष शिवजी राम यादव, जिला समन्वयक सीताराम शर्मा, गर्ल्स नॉट ब्राइड्स राजस्थान के राज्य सचिवालय (कल्प) के राजन एवं पूतम जोनवाल ने किया।

30 वर्ष पुराने प्रकरण में मौके पर निस्तारण से मिली राहत



द्वारा अनुशंषा की जाएगी। उन्होंने बताया कि महोत्सव में एकल एवं सामूहिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक सदस्य को जिला स्तर पर एक-एक हजार एवं संभाग स्तर पर 1500-1500 रूपये दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान वालों को 50-50 हजार रूपये, द्वितीय स्थान वालों को 25-25 हजार रूपये तथा तृतीय स्थान वालों को 10-10 हजार रूपये के पुरस्कार राजस्थान कला-रत्न लोगों सहित स्मृति चिन्ह पुरस्कार, प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा

द्वारा अनुशंषा की जाएगी। उन्होंने बताया कि महोत्सव में एकल एवं सामूहिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक सदस्य को जिला स्तर पर एक-एक हजार एवं संभाग स्तर पर 1500-1500 रूपये दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान वालों को 50-50 हजार रूपये, द्वितीय स्थान वालों को 25-25 हजार रूपये तथा तृतीय स्थान वालों को 10-10 हजार रूपये के पुरस्कार राजस्थान कला-रत्न लोगों सहित स्मृति चिन्ह पुरस्कार, प्रशस्ति प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा

कन्ज्यूमर केयर अभियान 7 प्रतिष्ठानों पर की गई कार्यवाही

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। कन्ज्यूमर केयर अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को 7 प्रतिष्ठानों पर जांच कार्यवाही की गई। जिला रसद अधिकारी नीरज कुमार जैन ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री नहीं करने इत्यादि की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए गए। प्रथम निरीक्षण दल में भावना दयाल सहायक निबंधक विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामले विभाग, हेमन्त कुमार अर्या प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बड़या प्रवर्तन निरीक्षक शामिल रहे। उन्होंने बताया कि कन्ज्यूमर केयर अभियान के जांच दल द्वारा पंडित ब्रदीप्रसाद नारायण प्रसाद, पंडित ब्रदीप्रसाद नारायण प्रसाद नारायण प्रसाद, राजस्थान नमकीन एण्ड स्वीट्स, सीताराम दूध वाला,

कन्ज्यूमर केयर अभियान 7 प्रतिष्ठानों पर की गई कार्यवाही

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। कन्ज्यूमर केयर अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को 7 प्रतिष्ठानों पर जांच कार्यवाही की गई। जिला रसद अधिकारी नीरज कुमार जैन ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री नहीं करने इत्यादि की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए गए। प्रथम निरीक्षण दल में भावना दयाल सहायक निबंधक विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामले विभाग, हेमन्त कुमार अर्या प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बड़या प्रवर्तन निरीक्षक शामिल रहे। उन्होंने बताया कि कन्ज्यूमर केयर अभियान के जांच दल द्वारा पंडित ब्रदीप्रसाद नारायण प्रसाद, पंडित ब्रदीप्रसाद नारायण प्रसाद नारायण प्रसाद, राजस्थान नमकीन एण्ड स्वीट्स, सीताराम दूध वाला,

ग्रामीण सेवा शिविर-2025 : आमजन की समस्याओं का हुआ त्वरित समाधान



चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर-2025 आमजन के लिए राहत और समाधान का माध्यम बन रहे हैं। शिविरों के माध्यम से राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों की लम्बित समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत कुंवाल्या में आयोजित शिविर में राजस्व विभाग द्वारा एक लंबे समय से लंबित भूमि विवाद का आपसी सहमति से समाधान कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई। ग्राम कुंवाल्या निवासी दल्ला पिता कजोड़ के परिवार के सदस्यों के बीच भूमि स्वामित्व को लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा था। ग्रामीण सेवा शिविर में दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात विभागीय अधिकारियों ने संधा स्थापित कर आपसी सहमति से भूमि का

विभाजन करवाया। नियमानुसार दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अब सभी पक्ष अपनी-अपनी भूमि के स्वामित्व अधिकारों के साथ स्वतंत्र रूप से कृषि कार्य कर सकेंगे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मण्डपिया में आयोजित शिविर के दौरान एक काशतकार के राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि का मामला सामने आया। विभागीय टीम ने मौके पर रिकॉर्ड का परीक्षण कर त्रुटि की पुष्टि होने पर तत्काल सुधार की कार्यवाही की। सुधार के पश्चात काशतकार को अपने भूमि संबंधी अधिकारों की विधिवत पुष्टि प्राप्त हुई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “ग्रामीण सेवा शिविर के कारण वर्षों पुरानी परेशानियां कुछ ही मिनटों में दूर हो गईं। यह वास्तव में आमजन के द्वार पर पहुंचा प्रशासन है।”

सिर्फ 25 की उम्र में ओलंपिक चैंपियन ने लिया संन्यास

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया की सबसे सफल तैराकी में से एक, ऑस्ट्रेलिया की एरियान टिटमस ने सिर्फ 25 साल की उम्र में तैराकी से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया है। चार बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टिटमस ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब उनके जीवन में कुछ चीजें तैराकी से ज्यादा अहम हो गई हैं।

पेरिसओलंपिक में रवा था इतिहास

एरियान टिटमस ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 400 मीटर फ्रीस्टाइल में अमेरिका की दिग्गज तैराक केटी लेडेकी और कनाडा की समर मैकिन्टोश को पछाड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। खास बात यह रही कि

खत्म हुआ एरियान टिटमस का सुनहरा करियर

टिटमस के नाम कुल 33 अंतरराष्ट्रीय पदक दर्ज हैं। इनमें 4 ओलंपिक स्वर्ण, 3 रजत, और 1 कांस्य शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने चार विश्व खिताब भी अपने नाम किए। उन्होंने न केवल अपनी देश की उम्मीदों पर खरा उतरा बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला तैराकी में एक नया मानदंड स्थापित किया।

उन्होंने इस इवेंट में नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था।

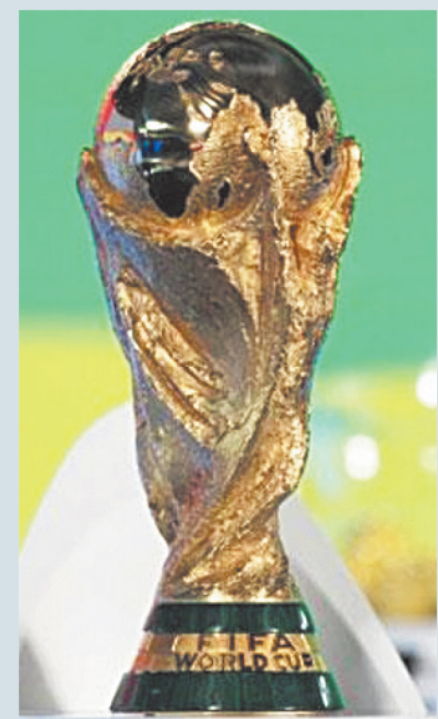
अब खेल से बाहर नई शुरुआत की तैयारी

हालांकि एरियान टिटमस के कोच और प्रशंसक उम्मीद कर रहे थे कि वह 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में वापसी करेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नया रास्ता चुन लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वह इस जीवन के नए अध्याय को लेकर उत्साहित हैं।



तयों लिया संन्यास का फैसला?

टिटमस ने अपने बयान में कहा, मुझे हमेशा से ही तैराकी में बेहद रुचि रही है। बचपन से ही ये मेरा सपना और जुनून रहा है, लेकिन अब जब मैंने थोड़ा वक्त इस खेल से दूर बिताया, तो महसूस किया कि जीवन में और भी बहुत कुछ है, जो मेरे लिए अब ज्यादा मायने रखता है। उनके इस बयान ने फैंस को भावुक कर दिया है।



फीफा को लेकर फैंस में भारी क्रैज, विश्व कप 2026 के 10 लाख से अधिक टिकट बिके

मियामी, एजेंसी। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने इस महीने की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर टिकट बिक्री शुरू होने के बाद से अपने पहले अपडेट में बताया कि अगले साल होने वाले विश्व कप के 10 लाख से अधिक टिकट बिक चुके हैं। उम्मीद के मुताबिक सबसे अधिक मांग अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के खरीदारों की ओर से रही। ये तीन देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। फीफा ने कहा कि 212 अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के लोग पहले ही टिकट खरीद चुके हैं जबकि अभी टूर्नामेंट के लिए 48 में से केवल 28 ही टीम तय हुई हैं। फीफा ने कहा कि टिकट खरीदने के मामले में शीर्ष 10 देश में इंग्लैंड, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, कोलंबिया, अर्जेंटीना और फ्रांस भी शामिल हैं। यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा। फीफा अध्यक्ष जियानो इन्फेन्टिनो ने विज्ञप्ति में कहा, 'दुनिया भर की राष्ट्रीय टीमों ऐतिहासिक फीफा विश्व कप 2026 में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और मुझे खुशी है कि इतने सारे फुटबॉल प्रेमी भी उत्तरी अमेरिका में इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'यह एक अविश्वसनीय प्रतिक्रिया है और एक अद्भुत संकेत है कि इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे समावेशी फीफा विश्व कप दुनिया भर के समर्थकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। फीफा ने यह भी घोषणा की कि उसकी 'रीसेल साइट खलु गई है और न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में विश्व कप फाइनल के टिकट बूहस्पतिवार दोपहर तक 9,538 डॉलर से लेकर 57,500 डॉलर प्रति सीट की कीमत पर उपलब्ध थे।

नाओमी ओसाका के लगी चोट, जापान ओपन के क्वार्टर फाइनल से हटीं



ओसाका, एजेंसी। नाओमी ओसाका बाएं पैर में चोट के कारण शुरुआत में जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल क्वार्टर फाइनल से हट गईं। मैच से पहले ओसाका के हटने से जैकलिन क्रिस्टियन को वाकओवर मिला और वह सेमीफाइनल में पहुंच गईं। डब्ल्यूटीए टूर ने यह जानकारी दी। टूर्नामेंट के आयोजकों ने कहा कि शरीर वरीय ओसाका दूसरे दौर के मैच के दौरान लगी चोट से नहीं उबर पाईं। क्रिस्टियन ने इस साल तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। चोट के कारण बाहर होने से पहले ओसाका ने क्वाना सोनोबे और 2024 की चैंपियन सुजेन लेमेस को हराया। जापान ओपन के एक क्वार्टर फाइनल में शुकुवार को अमेरिकी ओपन 2021 की उप विजेता लेला फर्नांडिज ने रेबेका रैमकोव को 7-6, 6-3 से शिकस्त दी।



विराट-रोहित दोनों वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे...

ट्रेविस हेड ने जैसे ही ये कहा अक्षर पटेल का चेहरा बदल गया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से पर्थ में हो रहा है। इस सीरीज से पहले ट्रेविस हेड और अक्षर पटेल ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर सवाल पूछा गया। ट्रेविस हेड से पूछा गया कि ये ऑस्ट्रेलिया में विराट और रोहित दोनों की आखिरी सीरीज हो सकती है तो इसपर उन्होंने कहा कि उनके साथ खेलना सम्मान की बात है। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद जताई कि ये दोनों दिग्गज 2027 वर्ल्ड कप भी खेलें। हालांकि ट्रेविस हेड के इस बयान के बाद अक्षर पटेल की जो भाव भंगिमा बदली उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ट्रेविस हेड ने क्या कहा?

ट्रेविस हेड ने मीडिया से बातचीत में विराट और रोहित दोनों की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'रोहित और विराट दोनों सफेद गेंद के खेल के महान खिलाड़ी हैं। विराट कोहली शायद सर्वकालिक महान वनडे क्रिकेटर हैं और रोहित भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। उनके लिए काफी सम्मान है। मुझे लगता है कि दोनों वर्ल्ड कप 2027 खेलने वाले हैं। खेल के लिए बहुत अच्छे होंगे।' ट्रेविस हेड ने जैसे ही ये कहा, गंभीर भाव से इस बात को सुन रहे अक्षर पटेल अचानक मुस्कुराने लगे। उन्होंने दोनों के वर्ल्ड कप 2027 खेलने के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा लेकिन इस ऑलराउंडर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि रोहित और विराट वनडे सीरीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं।

अक्षर ने विराट-रोहित पर क्या कहा?

अक्षर पटेल ने कहा कि विराट और रोहित जानते हैं कि दोनों को क्या करना है। उन्होंने कहा, 'विराट-रोहित दोनों वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। दोनों प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, जानते हैं कि क्या करना है, वो तैयार हैं। अगर आप उनकी फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो तैयार हैं। सभी खिलाड़ियों ने अपना फिटनेस टेस्ट दिया है और सीरीज के लिए तैयारी पूरी है।'

भारत के खिलाफ ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को करारा झटका

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले करारा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया कुल मिलाकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि उनके कई स्टार खिलाड़ी पहले ही सीरीज से बाहर हैं। अब इंजरी के कारण यह स्टार ऑलराउंडर भी बाहर हो गया है।



दरअसल, अ टीम के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोट के कारण तीन मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। ग्रीन को ट्रेनिंग के दौरान हल्की साइड स्ट्रेन (पेट के पास खिंचाव) की शिकायत हुई थी, जिसके चलते वे नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया है। सीरीज की शुरुआत रविवार (19 अक्टूबर) से पर्थ में हो रही है। मार्नस लाबुशेन को शुरू में ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं मिली थी, लेकिन घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के चलते अब उन्हें मौका दिया गया है। कैमरन ग्रीन की यह नई चोट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका है। हाल ही

स्टार ऑलराउंडर बाहर...

विराट कोहली संग खेलने का टूटा था सपना, अब डेब्यू पर एमबीएस्टूडेंट ने जड़ा दोहरा शतक

नई दिल्ली, एजेंसी। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली की टीम अपना पहला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ खेल रही है। हैदराबाद के नेक्सजेन क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे एलीट ग्रुप-डी के इस मुकाबले में दिल्ली के बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली ने अपनी पहली पारी 529/4 के स्कोर पर घोषित की। दिल्ली की तरफ से युवा बल्लेबाज आयुष दोसेजा ने 279 गेंदों पर 209 रनों की पारी खेली, जिसमें 25 चौके और पांच छक्के शामिल रहे। आयुष का ये फर्स्ट क्लास में डेब्यू मुकाबला है, जिसे उन्होंने यादगार बना दिया। दिल्ली के लिए सनत सांगवान ने भी दोहरा शतक जड़ा।

319 रनों की साझेदारी की, जिसने दिल्ली को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।



अभिनव ने 320 गेंदों का सामना करते हुए 2025 रन बनाए, जिसमें 21 चौके और चार छक्के शामिल रहे। एक ही दिन दो डेब्यूटेंट बल्लेबाजों का दोहरा शतक बनाना रणजी इतिहास की एक दुर्लभ घटना मानी जा सकती है।

कोहली के साथ ना खेल पाने का दर्द बरकरार

आयुष दोसेजा ने कहा कि विराट कोहली के साथ खेलने का मौका छिन जाना उनके लिए काफी दुःख था, लेकिन उन्होंने उसे ही प्रेरणा बना लिया। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, क्रिस्मट के अपने इरादे थे। विराट सर के साथ खेलने का मौका बस आया और चला गया। लेकिन रणजी डेब्यू पर दोहरा शतक लगाना उस दर्द को काफी हद तक कम कर गया। आयुष दोसेजा ने इस इनिंग्स का श्रेय साथी खिलाड़ी सनत सांगवान को भी दिया। दोसेजा कहते हैं, हमने अंडर-23 और अंडर-24 क्रिकेट एक साथ काफी खेला है। हमें पता था कि अगर सकारात्मक तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो रन अपने-आप आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि आयुष क्रिकेट के साथ-साथ स्क्वॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं। आयुष दोसेजा ने बताया, मैं मेरठ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा हूँ।

क्रिकेट का नया फॉर्मेट इस दिन होगा लॉन्च, ये हैं नियम

नई दिल्ली, एजेंसी। क्रिकेट में आए दिन कोई न कोई बदलाव होते रहते हैं, लेकिन इस बार एक नए फॉर्मेट का जन्म हुआ है। जो क्रिकेट के रोमांच को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसके लिए वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी सर क्लाइव लॉयड, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन और टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह को टेस्ट ट्वेंटी फॉर्मेट के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया। इसके अलावा

राजस्थान रॉयल्स के पूर्व सीईओ माइकल फोर्डहम को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

क्या है नया फॉर्मेट? टेस्ट ट्वेंटी फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट के पहलुओं को टी20 के साथ मिलाने की कोशिश करेगा। ये दुनिया का पहला 80 ओवर का फॉर्मेट होगा। हालांकि दोनों टीमों को एक साथ 40 ओवर खेलने के बजाय उनको 20-20 ओवर की दो पारियां खेलने का मौका मिलेगा।



इसके लिए प्रत्येक टीम दो बार बल्लेबाजी करेगी, ठीक वैसे ही जैसे टेस्ट मैच में होता है। इसमें टेस्ट और टी20 क्रिकेट दोनों के नियम लागू होंगे। इसमें सभी चार

परिणाम जीत, हार, टाई या ड्रा संभव हो सकते हैं।

टेस्ट ट्वेंटी कब शुरू होगा? टेस्ट ट्वेंटी का पहला सीजन जनवरी 2026 में शुरू होगा। इसमें

6 फ्रैंचाइजी हिस्सा लेंगी। जिनमें से तीन भारत से और तीन दुबई, लंदन और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रत्येक टीम में 16 खिलाड़ी होंगे। इस नए फॉर्मेट का आधिकारिक उद्घाटन 16 अक्टूबर किया गया। टेस्ट ट्वेंटी द वन वन सिक्स नेटवर्क के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव बहिरवानी के दिग्गज की उपज है। इस फॉर्मेट का पूर्व क्रिकेटरो में काफी तारीफ की है। पूर्व खिलाड़ियों ने क्या कहा: उध अफ्रीका के पूर्व

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में खींचतान, 10 सीटों पर उम्मीदवार आमने-सामने

-अमित शाह का बिहार दौरा: लालू के 'जंगलराज' वाले बयान पर BJP की तैयारी तेज

नई दिल्ली/पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई। इस चरण में कुल 121 सीटों पर मतदान होगा, जो 6 नवंबर को संपन्न होगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद और खींचतान जारी है। इस चरण में कांग्रेस और RJD के बीच मतभेद स्पष्ट रूप से दिखे, वहीं कुछ सीटों पर पार्टियों ने आपस में सीधे मुकाबला करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने इस बार अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने 48 सीटों पर अपने कैंडिडेटों का ऐलान किया है। वहीं, CPI (ML) ने 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसके विपरीत, RJD ने अभी तक अपने किसी भी उम्मीदवार की सूची सार्वजनिक नहीं की है। VIP (विकासशील इंसान पार्टी) ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। नामांकन की अंतिम तारीख तक, RJD, कांग्रेस और VIP अपने-अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांटते रहे। हालांकि महागठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा अब भी विवादास्पद बना हुआ है। 10 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। इनमें पाँच सीटों पर कांग्रेस और RJD के उम्मीदवार आमने-सामने हैं। तीन सीटों पर CPI और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। वहीं, एक सीट पर VIP

और RJD के उम्मीदवार आमने-सामने हैं। इस खींचतान के बीच VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने घोषणा की है कि वे इस की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय बिहार दौरे पर हैं। वे 16 से 18 अक्टूबर तक राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने पटना के ज्ञान भवन में प्रबुद्धजन सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में उन्होंने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि लालू यादव नए चेहरे और नए कपड़े बदलकर फिर से बिहार में 'जंगलराज' लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह ने कहा कि इसे रोकने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से काम करना होगा। पटना में शाह की मौजूदगी को राजनीतिक महत्व संकेत माना जा रहा है। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। उनके दौरे का उद्देश्य केवल प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जोश और अनुशासन में बांधना भी है। शाह का यह संदेश साफ है कि महागठबंधन की खींचतान के बीच BJP और उसके सहयोगी पार्टियों को मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। विश्लेषकों का कहना है कि महागठबंधन की खींचतान इसके चुनावी प्रदर्शन पर असर डाल सकती है। कई सीटों पर अगर कांग्रेस और RJD के उम्मीदवार आमने-सामने हैं, तो इससे वोट का बंटवारा होगा और एनडीए को लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।



दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में आग: सांसदों के फ्लैट में मची अफरा-तफरी

-फायर ब्रिगेड पर देरी का आरोप

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के केंद्र में शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बीडी रोड स्थित सांसदों के लिए बने ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यहां कई राज्यसभा सांसदों और उनके स्टाफ के आवास हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ लगाई। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने की सूचना तुरंत दिल्ली फायर सर्विस को दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंची। एक स्थानीय निवासी ने कहा, "हमने आग लगते ही 101 पर कॉल किया, लेकिन गाड़ियां लगभग 20 मिनट बाद पहुंचीं। अगर थोड़ा और देर होती तो हालात और गंभीर हो सकते थे।" वहीं, दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने जानकारी दी कि उन्हें दोपहर करीब 1 बजकर 22 मिनट पर कॉल मिली थी। सूचना मिलते ही छह दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। फायरमैनो ने कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। देखते ही देखते लपटें ऊपर तक फैल गईं और धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया। कई सांसदों और उनके परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें काले धुएँ के गुबार और आग की तेज लपटें साफ दिखी दे रही हैं। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि लोग घबराहट में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जबकि पुलिस और दमकलकर्मी उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और हादसे में किसी की लापरवाही पाई जाने पर कार्रवाई की जाएगी। फायर विभाग के अनुसार, आग पर करीब एक घंटे की मेहनत के बाद काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की धीमी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वीआईपी इलाके में सुरक्षा और इमरजेंसी सेवाएं बेहद तेज होनी चाहिए, लेकिन इस बार तंत्र की तैयारी सवाल के घेरे में आ गई है। फिलहाल, ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट परिसर को खाली करा दिया गया है और आसपास के क्षेत्र को पुलिस ने घेर लिया है। विद्वत् विभाग ने भी एहतियात के तौर पर पूरे अपार्टमेंट की बिजली सप्लाई बंद कर दी है।



"पाकिस्तान की ज़मीन 25 करोड़ पाकिस्तानीयों के लिए है, अफगान लौटें अपने मुल्क"

का बुल / इस्लामाबाद (ए.जे.सी.)। पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख।जा।आसिफ ने हालिया बयान में कहा है कि जो अफगान नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। आसिफ ने इंटरव्यू में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 'हमारी ज़मीन 25 करोड़ पाकिस्तानीयों के लिए है' और अब पाकिस्तान उन अफगानों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। उनके शब्दों में, 'अगर अफगानिस्तान के लोग हिंदुस्तान से इतने रिश्तेदार महसूस करते हैं तो वो इंडिया में क्यों नहीं शिफ्ट होते।' आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पुराने ताल्लुक अब खत्म हो चुके हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले के मुकाबले अब दोनों देशों के बीच भरोसे और आपसी हमदर्दी कम दिखती है। बावजूद इसके, पाकिस्तान ने वर्षों तक पड़ोसी होने का फर्ज अदा किया और कई अफगानों को पनाह दी, मगर अब आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ने से यही सहनशीलता मुश्किल हो गई है। रक्षामंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास अपने



ही लोगों के लिए सीमित संसाधन हैं और अतिरिक्त आबादी को पालना मुश्किल है। हमारा देश अपने नागरिकों की पहली ज़िम्मेदारी निभाएगा, वे बोले। उनका तर्क रहा कि अगर भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते गहरे हैं तो अफगानी नागरिकों का बचाव और स्वागत वही कर सकता है। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान ने मदद की मगर अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के बयान क्षेत्रीय राजनीति और आर्थिक चुनौतियों की परछाई हैं। अफगान शरणार्थियों की वापसी पर वास्तविकता, सुरक्षा और मानवीय पहलुओं पर निर्भर करेगी। पाकिस्तान के निर्देशक रवेये से यह साफ है कि वे अब अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त दबाव कम करना चाहते हैं। हालांकि, अफगानियों की किस्मत और भी देशों की नीतियों तथा अंतरराष्ट्रीय बौद्धि पर निर्भर करेगी।

दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली: -AQI 350 के पार, ग्रेडेड रिस्पॉंस एक्शन लागू

नई दिल्ली। दिवाली के त्योहार से पहले ही दिल्ली की हवा प्रदूषण की गंभीर समस्या का सामना कर रही है। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 के पार पहुंच गया है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शनिवार सुबह 8 बजे राजधानी का औसत AQI 367 दर्ज किया गया। इसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण आनंद विहार में 370 रहा, जबकि अक्षरधाम में 369, वजीरपुर में 328 और जहांगीरपुरी में 324 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली में यह बढ़ता हुआ प्रदूषण कई कारणों का परिणाम है। ठंड के मौसम की शुरुआत, जलवायु की स्थिरता, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से होने वाला धूल और पड़ोसी राज्यों से आने वाले पराली के धुएँ ने मिलकर हवा को जहरीला बना दिया है। पराली जलाने की समस्या हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण का मुख्य कारण बनती है। इसके अलावा, दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल से भी वायु प्रदूषण में भारी इजाफा होता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉंस एक्शन प्लान (GRAP-I) लागू कर दिया है। ग्रेडेड रिस्पॉंस एक्शन प्लान एक नियामक प्रणाली है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक के विभिन्न स्तरों पर विशेष कदम उठाने के लिए बनाई गई है। आयोग के अनुसार, यह कार्रवाई तब की गई है जब क्षेत्र में AQI 211 तक पहुँच गया। इस योजना के तहत सरकारी और निजी संस्थानों को कर्मचारियों की छुट्टियों, निर्माण कार्यों पर रोक,



वाहनों की संख्या कम करने जैसे उपायों का पालन करना होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि AQI 300 से ऊपर पहुंचने पर हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में आती है और यह सभी लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ, आँखों और गले में जलन, श्वसन संबंधी रोगों में वृद्धि और हृदय रोगियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। हालांकि सरकार और संबंधित विभाग समय-समय पर विभिन्न उपाय कर रहे हैं, जैसे सार्वजनिक परिवहन बढ़ाना, धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव, पराली जलाने पर प्रतिबंध और एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल बढ़ावा देना, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। नागरिकों को भी अपनी ओर से सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल, बाहर कम निकलना, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल और पौधारोपण जैसे उपाय प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। विशेष रूप से, दिवाली के अवसर पर पटाखों के अत्यधिक इस्तेमाल से हवा में जहरीली गैसों का स्तर और बढ़ जाता है। इसलिए विशेषज्ञ और पर्यावरण संरक्षक लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे इस साल 'हरित दिवाली' का विकल्प चुनें। पटाखों की जगह इको-फ्रेंडली सजावट और दीयों का इस्तेमाल सुरक्षित विकल्प हो सकता है।

पंजाब DIG हरचरण भुल्लर गिरफ्तार: -पांच जगहों पर छिपाया था कैश और गोल्ड

चंडीगढ़। पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का नाम अब भ्रष्टाचार के बड़े मामले में सामने आया है। चंडीगढ़ की कोठी में उनके कब्जे से जब्त किए गए सबूतों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और बड़ी मात्रा में कैश, गोल्ड और शराब जमा कर रखी थी। CBI की टीम ने बताया कि DIG भुल्लर ने अपनी कोठी में कैश और गोल्ड पांच अलग-अलग जगहों पर छिपा रखा था। सूत्रों के अनुसार, DIG ने सबसे पहले बेड के नीचे कैश रखा था, जिससे किसी भी बाहरी व्यक्ति को शक न हो। इसके अलावा, क्रॉकरी की अलमारी के निचले हिस्से में भी कैश रखा गया था और उसे लॉक किया गया था। DIG ने अपनी दो अलग-अलग आलमारियों में सोना छिपाकर रखा था। इन सभी जगहों पर सामान इस तरह रखा गया था कि बाहर से देखने पर कोई भी अंदाजा न लगा सके। DIG भुल्लर की एक महीने की सैलरी लगभग 2.64 लाख रुपए थी, लेकिन उनकी जीवनी और संपत्ति से यह साफ हो गया कि वे अपनी आम सैलरी से बहुत अधिक लज्जरी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लुधियाना के समराला फार्माहाउस से बरामद शराब की बोतलों में से कई की कीमत 50 हजार रुपए से



अधिक थी। कुल मिलाकर, उनकी संपत्ति और जमा किए गए सामान से यह संकेत मिलता है कि DIG ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध धन अर्जित किया। CBI ने DIG भुल्लर और उनके एजेंट कृष्ण को 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। इससे पहले मंडी गोंडिगढ़ के स्ट्रेप कारोबारी आकाश बत्रा से 8 लाख रुपए की रिश्तत लेते हुए एजेंट कृष्ण को सेक्टर-21 से पकड़ा गया था। सूत्रों ने बताया कि कृष्ण DIG का प्राइवेट आदमी था और वह रिश्तत के लिए शिकार खोजता था। इस गिरफ्तारी के बाद CBI ने DIG को भी रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को DIG भुल्लर और कृष्ण को चंडीगढ़ की स्पेशल CBI कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। CBI

मामले की जांच जारी रखे हुए है और संभावित अन्य वित्तीय अपराधों की भी पड़ताल कर रही है। इस मामले ने पंजाब पुलिस और प्रशासन की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। DIG भुल्लर जैसी उच्च पदस्थ स्थिति में रहते हुए भ्रष्टाचार करने की घटना ने जनता में गहरी नाराजगी और चिंता पैदा कर दी है। यह मामला इस बात का भी संकेत है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी और पारदर्शिता आवश्यक है। इस गिरफ्तारी से यह संदेश भी गया कि चाहे कोई कितना ही ऊँचा क्यों न हो, कानून के सामने सभी बराबर हैं। CBI की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कदम के रूप में देखी जा रही है और इससे अन्य अधिकारियों में भी चेतना पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेन में आग: सरहिंद स्टेशन के पास AC बोगी में शॉर्ट सर्किट

-यात्री सुरक्षित, कई ट्रेनें प्रभावित

लुधियाना। पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा जा रही गरीब रथ ट्रेन (12204) शनिवार सुबह सरहिंद स्टेशन के पास आग लगने की घटना से दहल उठी। यह आग 19 नंबर AC बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। ट्रेन में लुधियाना सहित आसपास के कई व्यापारी और आम यात्री सफर कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार, 19 उठी। बोगी में मौजूद यात्रियों ने ही आग फैल गई। बोगी में सवार चैन खींच दी, जिससे ट्रेन तुरंत से फेलने की वजह से यात्रियों में सामान को वहीं छोड़कर ट्रेन से यात्रियों को हल्की चोटें आईं, है। कुछ यात्री अपने छोटे बच्चों उनके लिए यह स्थिति और भी मोबाइल फोन से आग की तस्वीरें साझा किए, जिससे इस घटना सकता है। सूचना मिलते ही टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं। घंटे की कड़ी मेहनत के बाद नंबर 19 पूरी तरह जलकर खाक नंबर बोगी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। रेलवे अधिकारियों ने जली हुई बोगी को अलग कर ट्रेन को तीन घंटे के अंतराल के बाद अंबाला की ओर रवाना किया। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी यात्री की जान नहीं गई। अंबाला डिवीजन के डिजिटल रेल प्रबंधक (डीआरएम) विनोद भाटिया भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की पुष्टि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना की विस्तार से जांच के आदेश दिए गए हैं और रेलवे ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी बोगियों की AC सिस्टम और बिजली कनेक्शन की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है। इस घटना का असर अन्य ट्रेनों पर भी देखा गया। अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस, गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, दिल्ली इंटरसिटी और जालंधर इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के संचालन में देरी हुई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से संयम रखने और संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। विशेषज्ञों के अनुसार, शॉर्ट सर्किट से ट्रेन में आग लगना दुर्लभ तो है, लेकिन यह बिजली उपकरणों की पुरानी स्थिति, रखरखाव की कमी या अचानक तकनीकी खामियों के कारण हो सकता है। रेलवे विभाग अब सभी AC बोगियों के वायरिंग सिस्टम और सर्किट ब्रेकर्स की जांच कर रहा है।



पूर्व ऑस्ट्रेलियाई PM बोले- भारत पर टैरिफ ट्रम्प की गलती

-पाकिस्तान के साथ नहीं भारत के साथ रिश्ता रखें

ऑस्ट्रेलिया (ए.जे.सी.)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने शुक्रवार को NDTV वर्ल्ड समिट में कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाकर बड़ी गलती की है। उन्होंने साफ कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर भारी व्यापारिक शुल्क (टैरिफ) लगाना एक 'रणनीतिक भूल' थी, जिसने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को कमजोर किया। एबॉट के मुताबिक, पिछले दो दशकों में अमेरिका ने भारत के साथ भरोसे और सहयोग का रिश्ता मज़बूत करने की दिशा में काफी प्रगति की थी, लेकिन ट्रम्प की नीति ने उस पर झटका दिया। उन्होंने अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों पर भी तीखी टिप्पणी की। एबॉट ने कहा कि 'अमेरिका के हित पाकिस्तान में नहीं, बल्कि भारत



जैसे लोकतांत्रिक और स्थिर देश के साथ गहरे रिश्तों में है।' उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने एक ओर आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का साथ देने का दावा किया, वहीं दूसरी ओर ओसामा बिन लादेन को सालों तक अपने देश में छिपा कर रखा। एबॉट ने कहा कि पाकिस्तान में भले अच्छे लोग हों, पर उसकी नीतियां भरोसेमंद नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत 21वीं सदी की सबसे बड़ी शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, तकनीकी प्रगति और मज़बूत लोकतांत्रिक ढांचा भारत को वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में ला सकता है।

'जुलाई चार्टर' पर बांग्लादेश में बवाल: संसद में घुसे प्रदर्शनकारी

-पुलिस से हिंसक झड़पें और आगजनी

ढाका (ए.जे.सी.)। बांग्लादेश की राजधानी ढाका शुक्रवार को भारी हिंसा की चपेट में आ गई। संसद के बाहर 'जुलाई चार्टर' पर हस्ताक्षर से पहले शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। देखते ही देखते सैकड़ों प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुसे गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। पुलिस ने कई बार भीड़ को चेतावनी दी, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए, तो आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों और नियंत्रण कक्ष में आग लगा दी। कई जगह तोड़फोड़ और झड़पें हुईं। 'जुलाई वॉरियर्स' नामक समूह और पिछले साल आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों का आरोप है कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शख



हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन में शहीद हुए छात्रों और युवाओं के अधिकारों की अनदेखी की है। हिंसा के बीच देशभर में तनाव फैल गया है। इसी दिन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनुस संसद में 'जुलाई चार्टर' पर हस्ताक्षर करने वाले थे। यह चार्टर शासन सुधार, भ्रष्टाचार खत्म करने और लोकतांत्रिक स्थिरता बहाल करने का रोडमैप है, जिसमें 80 से अधिक सिफारिशें शामिल हैं। विपक्षी पार्टी बीएनपी का कहना है कि इस चार्टर के कई प्रावधान संविधान के खिलाफ हैं और इससे संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि बिना जनसंवाद के इसे लागू करना अस्थिरता बढ़ा सकता है।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शांतिगंज सेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार्यालय 4312 मोहल्ला नायकों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मॉ. 08058969180 कार्यालय फोन- 0141-2609886.